[Shri Uttam Rathod]

also deprived the seasonal employment provided by the Ginning factories to the labourers and has also deprived the State Government of Sales Tax and its share in the Income-tax as most of the cotton was transported to the adjoining States by the Cotton growers in the hope of getting better price. It will not be out of place if I mention that the CCI at Adilabad and Barhanpur was purchasing cotton at market price prevailing there.

All these factors have created a great discontent among the cotton growers which, if not corrected, as assured by the Minister in time, will affect the area under cotton crop in Maharashtra.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further consideration of the following Motion of Thanks on the President's Address moved by Prof. N. G. Ranga:

> "That an Address be presented to the President in the following terms:—
>
> 'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 18th February, 1982.'"

Shri Ram Singh Yadav.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में कल भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयंभू नेता श्री जेठमलानी जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने इस संभाषण के सम्बन्ध में निराशा जाहिर की। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्न में इस सरकार ने जो प्रगति की है, सरकारी उद्योगों में जो उत्पादन की क्षमता 20 प्रतिशत बढ़ायी है, कोयले के उत्पादन को बढ़ाया है, ऊर्जा में 11.3 प्रतिशत की जो वृद्धि की है, हमारे निर्यात व्यापार में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि की है और इस के साथ-साथ ही खाद्यान्न तथा दूसरे उर्वरक आदि के उत्पादन की क्षमता बढ़ायी है, क्या सरकार के इन कार्यों से वे निराश हैं और क्या महामहिम राष्ट्रपति ने जो संकेत किया है कि हम आने वाले समय में उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, आने वाले वर्ष को उत्पादन वर्ष के रूप में मनाना चाहते हैं और आने वाले वर्ष में हम हर एक क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ायेंगे, क्या इस संकेत को और राष्ट्र के विकास के रथ को एक गति देने के लिए जो उन्होंने संकेत दिया है क्या उस संकेत को आप निराशा का संकेत मानते हैं ? मुझे ऐसा लगा कि यह निराशा सरकार के कार्यों के प्रति नहीं, सरकार की प्रगति के प्रति नहीं बल्कि यह निराशा उन की एक राजनैतिक निराशा है और मैं उन से कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, यह हमारी देन आप को नहीं है, बल्कि यह देन तो आप के आस पास में है। आप के ही साथ बैठे हुए जो लोग हैं उन की यह देन है और यह चीज आप को रहेगी। यह पोलिटिकल फ्रस्ट्रेशन जो आप का है इस की वजह से ही आप को सब जगह निराशा नज़र आती है। इसलिए जिस चश्मे से आप देख रहे हैं और जिस चश्मे से आप देख कर चलना चाहते हैं उस के कारण यह निराशा है और वास्तव में यह निराशा आप तक ही सीमित निराशा है। न यह निराशा

चाहते हैं उस के कारण यह निराशा है और वास्तव में यह निराशा आप तक ही सीमित निराशा है। न यह निराशा राष्ट्र में है, न राष्ट्र के नागरिकों में है और न यह निराशा सरकार में है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि एक सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे पहली आवश्यकता किस बात की होती है यदि आप इस देश के इतिहास को देखें तो आदि काल से तभी यह देश कमजोर हुआ जबकि बाहरी शक्तियों ने अपने पंजे फैलाए। कोई भी राष्ट्र सेना की शक्ति से बड़ा नहीं हो जाता हथियारों को इकट्ठा करने से बड़ा नहीं हो जाता बल्कि राष्ट्र तब बड़ा बनता है जबकि उसके पास सुदृढ़ मनोबल हो और आत्मविश्वास हो। राष्ट्र तब बड़ा बनता है जबकि उस राष्ट्र के नागरिकों में यह विश्वास हो कि उनको प्रगति करनी है और उनमें किसी प्रकार की कोई इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स नहीं है। आज विरोध पक्ष में बैठने वाले जो हमारे बंधु हैं वे हर क्षेत्र में इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स पैदा करना चाहते हैं। किसी भी देश के आत्मविश्वास और मनोबल के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि देश में एकता की भावना पैदा हो। राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सहयोग की भावना से काम करें। यदि देश को मजबूत करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र में एक सबल सरकार हो, स्टेबिल सरकार हो। जब तक केन्द्र में स्टेबिल सरकार नहीं होगी तब तक देश के नागरिकों का मनोबल मजबूत नहीं होगा। स्थायी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणादायक शक्ति यह है कि एक बहुत मजबूत नेतृत्व हो। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश को एक मजबूत नेतृत्व और एक सक्षम सरकार दी है।

1977 से 1980 के बीच में इस देश में जो सरकार रही उसके बारे में न केवल इस देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी हास्यास्पद बातें कही जाती थीं। उस सरकार में जो सब से बड़ी कमी थी वह यह कि उस का कोई मजबूत नेतृत्व नहीं था और उस के पास कोई निश्चित दिशा नहीं थी। उन्होंने आपस में बन्दरबांट की नीति अपना रखी थी।

कल यहां पर जेठमलानी जी बोल रहे थे तब पालियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि 1977 में जब प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनाव हुए तब उसके मुख्य मंत्रियों के लिए बन्दरबांट किया गया। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में जनसंघ, यू० पी०, बिहार में दूसरे घटक बी० एल० डी० और इसी प्रकार से दूसरे प्रान्तों में दूसरे घटकों को मुख्य मंत्री दिए गये। क्या प्रजातंत्र को चलाने की उन की यही स्वस्थ परम्परा थी? क्या इस प्रकार से ये स्वस्थ प्रजातंत्र कायम करना चाहते थे? मैं समझता हूं कि देश आजाद होने के बाद इतिहास में पहली बार यह सुनने को मिला कि प्रधान मंत्री कहता है कि गृह मंत्री भ्रष्ट है और गृह मंत्री कहता है है कि प्रधान मंत्री भ्रष्ट है। जिस दिन गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया उसके बाद 1 जुलाई, 1978 को कैलक्टा वीकली में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिस में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट में चारों ओर करप्ट लोग हैं। उनके एक्चुअल शब्द सुन कर आप को बड़ा ताज्जुब होगा।

[श्री राय सिंह यादव]

उस वक्त के गृह मंत्री ने अपने कुलीग्स के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए:

"I feel relieved. In the Government I was surrounded by many corrupt persons."

इस प्रकार के शब्द एक गृह मंत्री अपने प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों के लिए कहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कल जेठमलानी जी स्वस्थ डेमोक्रेसी की दोहाई दे रहे थे और उसके लिए नामर्स कायम करने की दोहाई दे रहे थे क्या जनता पार्टी के शासन में यही नार्म्स थे जिस में एक गृह मंत्री कहता था कि प्रधान मंत्री भ्रष्ट है और उसके साथ काम करने वाले दूसरे मंत्री भ्रष्ट हैं? क्या स्वस्थ प्रजातंत्र के यही नार्म्स हैं?

15.00 hrs.

मैं समझता हूं कि यही एक कारण था चूंकि आपके पास नेतृत्व नहीं था और न आपके सामने दिशा थी। आपको एक अवसर मिला था कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र इस देश के अन्दर कायम करते, लेकिन आप नही कर सके। यही कारण है कि आपने करप्शन के बारे में बहुत सी बातें कहीं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप करप्शन को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। क्या श्री एच० आर० खन्ना ने भी श्री बीजू पटनायक के खिलाफ, जो कि आपको पार्टी के, आपके दल के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास नहीं किए। जिस दिन श्री बीजू पटनायक कांग्रेस में थे, उस दिन वे भ्रष्ट थे और जिस दिन आप की पार्टी में शामिल हो गए, उस दिन वे गंगा जल की तरह पवित्र हो गए। इसी तरीके से श्री देवराज अर्स, जिस समय कांग्रेस में थे, कमीशन की उनके खिलाफ रिपोर्ट है, उस समय भ्रष्ट थे और कांग्रेस छोड़ने के बाद, जब वे आपके साथ आकर बैठ गए, वे भी पवित्र हो गए। वे बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप उनकी प्रशंसा करते हैं, और उनको आप पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं तथा यह कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि करप्शन को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? क्या आप ने श्री सी० ए० वैधलिंगम, जो कि एक रिटायर्ड जज है, उनकी रिपोर्ट को पढ़ा है? उनकी रिपोर्ट किस आधार पर प्राप्त हुई है, किसने मांगी थी वह रिपोर्ट, किसने वह कमीशन कायम करवाया था? जिन लोगों ने राज्य सभा में एक प्रस्ताव पारित कर के और उसका कमीशन कायम करवाया था, आज कहां गए वे लोग, जो यह कहते थे कि मेरे खिलाफ एक्शन करो और इन्क्वायरी करो। स्वयं चौ० चरण सिंह कहते थे कि मैं बिल्कुल पवित्र हूं, लेकिन श्री सी० ए० वैधलिंगम ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। श्री मोरारजी भाई यह कहते थे कि कातींभाई के खिलाफ कोई दोष नहीं है, लेकिन कान्ती भाई के लिए क्या कहा गया, उस रिपोर्ट में। श्री जेठमलानी आज करप्शन की दुहाई देते हैं, मैं उन से पूछना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जिनकी धर्मपत्नी के संबंध में व श्री मोरारजी भाई जिनके पुत्र कांतीभाई और उनकी पुत्रवधु पदमा के बारे में वैधलिंगम रिपोर्ट में जो प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में उनके पास कुछ कहने को है? ये उस समय के कार्य हैं, उस समय के कृत्य हैं, जिस समय वे प्रधान मंत्री थे और चौधरी चरण सिंह यहां पर गृह मंत्री थे। मैं आप से पूंछना चाहता हूं कि आप को और भी बहुत से मौके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये मिले, लेकिन उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये आपने क्या कदम उठाये?

आपने कहा कि भ्रष्टाचार के लिये डिफैक्शन भी एक कारण है । कल श्री भजनलाल का उदाहरण दिया गया । भजनलाल शुरू में कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस में मिनिस्टर थे आपने उनका आलिंगन किया और उनको गोद में बिठाया और बैठाकर उनको आपने पुरस्कार दिया, इस डिफैक्शन को किसने उत्साहित किया, किसने उसके लिये पुरस्कार दिया ? और अब जबकि श्री भजन लाल फिर अपने पुराने दल के साथ आ जाते हैं, तो आपको फिर उनके अन्दर भ्रष्टाचार नजर आता है, करप्शन नजर आता है । आपके करप्शन का नजरिया, आपके करप्शन का चश्मा, ऐसा चश्मा है जिसमें आपकी पार्टी का आदमी जो कि आप की तरफ बैठा हुआ है, चाहे वह कितना भ्रष्टाचार करे, चाहे उन के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स हो, चाहे हाईकोर्ट के फैसले हों, चाहे उनके खिलाफ कमीशन की रिपोर्ट हो, वह आपको नजर नहीं आती है, लेकिन आपको दूसरी तरफ करप्शन नजर आता है सत्ता पक्ष की तरफ का करप्शन आपको नजर आता है । करप्शन को दूर करने के लिये अभी 15 जनवरी 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक नया 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्मगलर्स के खिलाफ, करप्ट लोगों के खिलाफ, ब्लैक-मार्केटियर्स के खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करेंगे । क्या उस समय, जब आपकी गवर्नमेंट कायम थी, तीन साल तक, आप ने इस तरह की कोई घोषणा की ? आप के सामने एकही काम था, आपने प्रजातन्त्र की दुहाई दी, प्रजातन्त्र मजबूत करने के लिए कहा, आप को मौका मिला था कि अपोजीशन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और आपने उसको साबित करके दिखाया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से चुनाव जीत कर विपक्ष में बैठने के लिये संसद में आईं, लेकिन आप का प्रजातन्त्र यह कहता था कि विपक्ष में कोई मैम्बर आपके सामने आकर नहीं बैठ सकता है। विश्व के इतिहास में पहली बार जनता के चुने हुये नुमाइंदे को आप ने इस तरह से केवल सदस्यता से ही वंचित नहीं किया बल्कि उसको जेल भी भेजा । यह जनता द्वारा चुने हुये नुमाइदे के प्रति और विशेषकर उस व्यक्ति के प्रति जो देश का प्रधान मंत्री रह चुका था, सबसे बड़ा प्रमाण था । क्या यही आपकी परम्पराए हैं, क्या इन्हीं परम्पराओं को सामने रखकर डेमोक्रेसी के नाम पर श्रीमती इंदिरा गांधी से पूंछते हैं कि विस्थ परम्पराओं के लिए आप क्या करने जा रही हैं ? श्रीमती इंदिरागांधी 1980 से लेकर आज तक जो आप के कार्यक्लाप थे जो परम्परायें आपने कायम की थीं, जिस तरह से आपने कमीशन्ज बैठाने के काम किये थे, उन पर नहीं चली । आप ने किस बात के कमीशन्ज बनाये थे—क्या श्रीमती इंदिरा गांधी मणिपुर से कोई मुर्गी का चूंजा लाईं थीं ? उसके खिलाफ एन्क्वायरी की जाये ? और कल जो जेठमलानी साहेब यहां तरह-तरह की बातें कह रहे थे, यह जानते हुये कि श्रीमती इंदिरागांधी के खिलाफ वे चार्जेज झूठे थे, एक एडवोकेट की हैसियत से शाह कमीशन के सामने परवी करते थे । यही आपकी प्रजातांत्रिक परम्परायें हैं ? क्या इन्हीं पर आप प्रजातन्त्र को दृढ़ करना चाहते हैं, जिस नजरिये से आप प्रजातन्त्र को देखना चाहते हैं, जिस नजरिये से आप भ्रष्टाचार को देखना हैं जिस नजरिये से आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं वे आप तक ही सीमित रहें तो बेहतर होगा । हम लोगों का नजरिया आपके नजरिये से अलग है और वह यह है कि आज हमारे राष्ट्र की नेता और देश की प्रधान मंत्री ने आप से सहयोग की अपील की है । वे आप से इस बात के लिये सहयोग मांगती हैं कि आज हमारे सामने कुछ चेलेन्जेज हैं, साष्ट्र के सामने कुछ चुनौतियां हैं और वे इस तरह की चुनौतियां हैं जो केवल देश तक ही सीमित नहीं हैं, वे चुनौतियां विश्व के सामने हैं, सारा विश्व आज उनका सामना करने के लिये तिलमिला रहा है तड़फड़ा रहा है और मुकाबला करने के लिये आपको भी आगे बढ़ कर पहल करनी है

हमें देखना है कि हमारे पड़ौसी देश में किस तरह से हथियार जमा हो र हैं । जनता

[श्री राम सिंह यादव]

पार्टी के नेता हथियारों के इस जमाखोरी के संबंध में कहते हैं कि पाकिस्तान में यदि हथियार जमा हो रहे हैं तो उनसे हिन्दुस्तान को डर नहीं लगना चाहिये । मैं पूंछता हूं—कि क्या ये हथियार नुमाइस के लिये इकट्ठे किये जा रहे हैं, हथियारों का इतना बड़ा जमाव क्यों किया जा रहा हैं ? आगा शाही साहब ने परसों क्या स्टेटमेंट दिया है ? वह कहते हैं कि अमरीका ने जब हथियारों की सप्लाई के बारे में अपनी पेशकश की तो उनकी प्री-कन्डीशन यह थी कि वहां पर अमरीका क मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दी जाये। उनका कहना है कि कि मुझे गर्व है कि मैंने उस प्री-कन्डीशन को स्वीकार नहीं किया । इससे साफ जाहिर है कि अमरीका की क्या नीयत थी ।

इन सब बातों को देखते हुये यदि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह संकेत दिया है कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाएं, सारे राष्ट्र के अन्दर एकता पैदा हो—तो क्या उनका यह सकेत सही नहीं है ? क्या इस 'अभिभाषण में जो सकेत दिया हुआ है वह सामयिक नहीं है ? थे समझता हू कि वह सामयिक है और देश को उसकी आवश्यकता है । हमारी नेता ने देश के सामने जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम रखा है ह उस दिनों में आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाता है । आप कहते हैं—महगाई बहुत बढ़ गई है, चीजों के भाव बढ़ गये हैं । लेकिन आप यह भी जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ा है, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में महगाई बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ा कर ही उस पर काबू पाया जासकता है। आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिये—यदि इन्फलेशन को कन्टेन करना चाहते हैं, कीमतों पर काबू पाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि हम देश का उत्पादन बढ़ायें । आज समय की आवश्यकता को देखते हुये, राष्ट्र क आवश्यकता क देखते हुऐ देश की प्रधान मन्त्री ने देश को ऐक नारा दिया है—"श्रमेव जयते ।" आज हमें श्रम की कीमत को समझना चाहिये । इस देश में जो आदमी अधिक से अधिक श्रम करता है उसको समाज ने कभी आदर नहीं दिया । एक मेंहतर जो अपने सिर जर मैला ढोता है वह आप के बराबर नहीं बैठ सकता एक व्यक्ति जो अधिक से अधिक मैनुअल वर्क करता है, जिसको आप छोटे से छोटा काम समझते हैं, उसको आप कभी अपने सामने बैठाना नहीं चाहते । देश का किसान जो अधिक से अधिक अन्न पैदा करता उसको आप कभी उतनी इज्जत नहीं देना चाहते जो एक व्हाइट-कालर्ड आदमी को देते हैं । इस लिये आज आवश्यकता है कि हम अपने सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को बदलें । सामाजिक मूल्यों को हम बदलें क्योंकि जब तक सामाजिक मूल्यों को नहीं बदलेंगे, जब तक समाज में हाथ से काम करने वाले व्यवितयों को उचित सम्मान नहीं देंगे, जब तक समाज में और सारे काम करने वाले व्यवितयों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक राष्ट्र का उत्पादन क्षेत्र पिछड़ा रहेगा । यह बड़ी खुशी की बात है कि आज एक नारा दिया गया है और वह नारा यह है कि सन् 1982 वर्ष को प्रोडक्टिविटी इअर, उत्पादन का इअर मनाया जाए और इस साल में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए । कल हमारे एक साथी पूछ र थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और सत्ताधारी पक्ष किस बात का हम से आवाहन करता है, किस बात लिए कोआपरेशन चाहता है । मैं वताना चाहता हूं कि आपका कोअपरेशन चाहते हैं देश का उत्पादन बढ़ाने में, आप का कोआपरेशन चाहते है कि हमारे देश में जो शर्मनाक घटनाएं होती हैं वे न हों, जो असामाजिक तत्वों द्वारा कम्युनल रायट्स होते हैं, वे कम्युनल राइट्स न हों और उन को रोकने के लिए हम और आप मिल कर काम करें । आप का सहयोग इस बात के लिए भी हम चाहते हैं कि इस देश के अन्दर जो असामाजिक तत्व ग़रीब हरिजनों, ग़रीब आदिवासियों को एक्सप्लायट करते हैं, जो उन का शोषण

करते हैं, जो उन पर अत्याचार करते हैं, उनको दूर करने के लिए हम और आप मिल कर, कन्धे से कन्धा मिला कर काम करें। हम आपका सहयोग चाहते हैं विषमताओं को दूर करने के लिए और जो अन्याय ग़रीब लोगों पर होता है, उस अन्याय के खिलाफ हम और आप मिल कर लड़ाई करें। देश के अन्दर जो ब्लैक-मार्केटियर्स हैं, जो एण्टी-सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ़ एक जिहाद बोलें और उनके खिलाफ हम मिल कर काम करें। जो रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं, वे कन्ज्यूमर स्टोर्स के जरिए और दूसरी सप्लाई लाइन के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक को आसानी से मिल जाएं। इस काम के लिए मुहल्ला कमेटी हो, शहर की कमेटी हो या गांव की कमेटी हो, जो इसके ऊपर निगरानी रखे। इस में हम आपका सहयोग चाहते हैं और आपका सहयोग इस बात में भी चाहते हैं कि हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बने। हम और आप मिल कर इस देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाएं, जिससे किसी भी राष्ट्र को हमारे देश में के बारे में कोई भी ग़लत कदम उठाने की इच्छा न हो।

इसलिए मैं यह कहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से विरोधी पक्ष के लोगों से सहयोग की जो अपील की है, विरोधी पक्ष के लोगों से राष्ट्र उत्पादन बढ़ाने की जो अपील की है, विरोधी पक्ष के लोगों से देश में जो सामाजिक अन्याय है, उस अन्याय को दूर करने की जो अपील की है, वह एक सामाजिक अपील है और मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में इससे अधिक अच्छा अभिभाषण राष्ट्रपति जी का नहीं हो सकता था। इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं और अपने साथियों से उम्मीद करता हूं कि उसके अनुरूप वे व्यवहार करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri E. Balanandan. CPIM party has been alloted 42 minutes. You will be followed by Shri Satyasadhan Chakraborty.

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have listened and gone through the Speech of Rashtrapati; I have also heard my hon. friend, Prof. Ranga. From the way the issues have been presented in Rashtrapati's speech, the policy which has been pursued by the Government last year and the new policy which has been projected for this year through the speech, it is very distressing to find that in the whole thing, the main issues faced by the country are being under-played.

Before I refer to the other points, I would first like to say that the ruling party is trying to give a go-by to this Parliament itself. A few days before the Parliament was to begin its session, we heard of an announcement from the Minister of Communication about the position of levy on telecommunication system, amounting to several crores of rupees. This question was raised in the Rajya Sabha, and the hon. Chairman, Rajya Sabha, made an observation on this and with your permission, I would like to quote it here:

> "I personally think that propriety demands that, if there is an increase in the rates of levies of this type, it should be done not on the eve of the budgetary session, but well in advance, so that the people will know that this is not a part of the budget being showed in (*Interruptions*)..You raise more funds by an executive order. To that extent the budgetary levies can be reduced. That is the point. I think there is something in what the opposition feels that these should be brought as a part of the budgetary discussion...."

What did the hon. Speaker of this House say last time when Shri Pande

[Shri E. Balanandon]

first introduced this kind of levies for the railways? He pointedly said it should be brought in the form of a Supplementary Demand and that direction from the Chair has not been taken note of seriously by the Ruling Party.

Again technically they may say, it is legally within our right and we who are here in Parliament are coming to discuss the Budget and the total Government policy on the taxes and revenues etc. etc. But this is being imposed. As soon as it comes, this is done. This is one part of it. The Ruling Congress (I) Party has sufficient majority. There is no dearth of people here who can put their arguments congently. We may argue something and convince this House. This is absolutely necessary, so that we all respect the Parliamentary democracy.

Rangaji is a great man. I agree, but Rangaji do you expect the Parliament is to be taken this way?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): He was a Member of the Constituent Assembly.

SHRI E. BALANANDAN: Rashtrapati, in his Republic Day message, said that transgressing the Constitution will bring in confusion in the country. So, he has warned that transgressing the Constitution will bring confusion in the country. Against whom was he giving this warning? Of course, we are not doing anything against the Constitution as such. We are always fighting for the Constitution. But then who is doing it? He was, perhaps, thinking of the policies of the Ruling Party in the country.

Take for example Kerala. What is going on there now? Jyoti Venkatachalam, the great Governor of the Kerala State found one day that out of the Assembly strength of 141, 67 is the majority.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: New mathematics.

SHRI E. BALANANDAN: New mathematics. We don't understand this thing. In the Assembly it was proved without doubt that the Janata Party said: We did not give support to Mr. Karunakaran and his colleagues when they were going in for the formation of the Government there.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Are we discussing Kerala issue?

SHRI E. BALANANDAN: Then another example about Assam. Here another mathematics will come. In the Assam, Assembly the total strength is 119. The Left and Democratic Fronts formed an Alliance; Sixtyfour MLAs of the Alliance went to the Governor saying that we are willing to form a Government. But the Governor in Assam could not find 64 in majority out of the total strength of 118. This is a new mathematics that is coming in.

And what is going on in Kerala? Corruption is being opposed by all in the public, but horse-trading is a part of the game being carried out, I must say, by the Congress Party in politicking. There in Kerala, afterall this a Government is going on minus the Speaker, having a strength of 70, and the Speaker is always supposed to...

SHRI XAVIER ARAKAL: Sir, I am on a point of order. Under Rule 352, the Member while speaking, should not impute motive to any matter related to the State Government. Now, the Hon. Member, is directly or indirectly debating a subject which is forbidden under that Rule.

SHRI E. BALANANDAN: It is not entirely within the scope of the

State Legislature. I am prepared to argue on this point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: On Rule 352, I would only request Mr. Balanandan that there should not be any reflection on the Speaker of the Kerala Assembly.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): What reflection? He is only stating the facts.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It should not be any reflection.

PROF. MADHU DANDAVATE: I am on a point of order.

Sir, I am quite conscious of Rule 352. But, at the same time if any hon. Member comes to the assessment that the Constitutional breakdown is there or Constitutional provisions are not being respected or Constitution in letter and spirit is not being followed, in that case reference to that particular situation is perfectly in order.

SHRI E. BALANANDAN: I was not saying anything against the Speaker as such. I was speaking on transgressing the Constitution. That is what I was saying. There what happened? In the history of Parliamentary democracy of the world this kind of a situation never came about. It is for you, you can defend it.

In Assam, what happened? Left and Democratic Alliance people came and met Rashtrapatiji. With your permission, I will read here a portion of the Memorandum they have submitted to Rashtrapati.

"Conclusion: In our viws. Shri Prakash Mehrotra, Governor or Assam, by his action has struck at the very base of Parliamentary democracy. All his accents are in tune with the authoritarian character of the Ruling Party.

We the Members of the Constituent units who support the Left and the Democratic Alliance, bring to your notice and through you, to the Parliament and to the people of India, how in Assam (1) the Constitution has been subverted; (2) the people's right has been trampled down; (3) the tradition, convention and usual practice of the Parliamentary democracy has been brushed aside; (4) the Oath of Office has been broken by the Governor, who failed to defend the Constitution. Lastly, but not the least, the people's faith in the Constitution, the rule of law and democracy has rudly been shaken."

Therefore, when Rashtrapati in his Republic Day speech stated that any transgression on the constitution will bring in confusion, he referred to the policy of the Congress(I) Party here.

Then I invite your attention to Bengal affairs. Here in the discussion always Bengal comes in prominently. It is only natural. I have no grouse about it. But what is the main question now?

We are having a federal policy. The State Government have their own right; Centre, have their own right. With regard to elections, we have the Election Commission and the State Government has to say elections are to be conducted and the Election Commission may direct. That is the position under law. Now, what happened in West Bengal. The State Government wanted elections. Immediately a big row came. The electoral list is absolutely bogus. Then the Election Commission sent its official personnel to find out the truth. The whole cry was bogus, and the voters' list was found absolutely correct.

Then came the other thing: I don't want to mention it. My friends may object to it. What does it show? It

[Shri E. Balanandan]

shows only that the Congres (I) Party is not willing to face the electorate, either in Kerala or in West Bengal, or in Garhwal or in Delhi. They do not want to go in for elections. (*Interruptions*) I am stating this on the basis of facts. I am not making any unfounded allegation. In Karala, in Garhwal, Delhi and everywhere, I am sorry to say that this ruling party is afraid of the people.

In a federal polity, in the Central Government we may have the rule of one party; and in the States, some other party may come to power. When I go through some papers, I find that West Bengal Government is being discriminated against by the Central Government in the matter of supply of so many essential items—rice, wheat, cement, sugar etc. I have got evidence also. (*Interruptions*) Don't say this is wrong. I do not want to quote things. I have got evidence. The point is only this. (*Interruptions*) When we have the right to vote for any party to come to power, if any Central Government wants that a particular party should be voted to power, it will mean scuttling of democracy.

The West Bengal Government is discriminated against. The Chief Minister of West Bengal has written to Central Ministers quoting figures, (*Interruptions*)

Let us now come to Kerala. Even though Mr. Karunakaran is the so-called Chief Minister there (*Interruptions*) He is the Chief Minister; I stand corrected—(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: He has corrected himself.

SHRI E. BALANANDAN: The point I want to make here is that to Kerala also, sufficient food supplies are not given. We are having a foreign exchange crisis. Therefore, we have to develop what is called self-reliance, i.e. we have to restrict imports to the minimum. That will be in the national interest. But what do we find? We are having self-sufficiency with regard to cocoa, with regard to rubber and with regard to coconut oil. But all of a sudden we find that these things are allowed to be imported into this country. The consequence is that people of Kerala are suffering very much. (*Interruptions*) Kerala means the land of coconuts. To protect the interests of coconut growers, Government of India have now established a Coconut Board. That Board came into existence six months before. They have formulated a certain programme; and it has been sent to the Central Government. The Chairman of the Coconut Board is an important Cogress (I) leader. I do not want to name him. He has sent the Schemes to protect the Coconut growers of Kerala to the Government three months back. But the Ministry of Agriculture did not clear it.

Secondly, the Coconut Board has to be given some finances, to function. That has not been given. That is the way federal policy has been put into practice by Central Government.

You want to keep the nation intact, and want all the parties and all the people in the country to make every effort for furthering the interests of the country. Prof. Ranga has now said that the Opposition also should join in the effort of the Government. All right. In that case, Mr. Ranga, do you agree that this kind of discrimination, on the basis of political differences, should be there? When it is done, it is against the spirit of the Constitution.

Now about law and order. In paragraph 21 of the President's Address, it is said:

"I now turn to some problems concerning law and order. There

cannot be forward movement without the assurance that national energies are not frittered away on agitations engineered by sectional interest."

This is about the law and order problem. I completely disagree with this approach. About this question of 'interests', I will deal with later. Recently, our Prime Minister had occasion to go to West Bengal. She said that the law and order situation in West Bengal was very bad. She has a right to say anything. I don't dispute her right. But is the law and order situation in Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh very good? Let us see the figures.

The great Chhaviram—who is he, and what is he? He is a dacoit. What is to his credit? He has conducted 100 dacoities in U.P. alone. He has killed 88 persons, including women and children. This great Chhaviram has conducted a 4 day *puja* and so many thousands of people assembled. You know there is a prize of Rs. 1.5 lakhs on his head. What happened? Four days after the *puja*, Chhaviram went away; and it was said that some kind of an arrangement was there between the local MLA or MP who is a high-up, so that the police could not do anything. That is where the dacoits and the ruling party—I would say some leaders of the ruling party—had some kind of a connivance and connection with these kinds of dacoits in the State of U.P.

Is it there only in P.P.? I don't want to cite examples of reports coming in daily newspapers. With your permission, I will give only one quotation. I will read a reproduction of an item in '*Blitz* dated 5-12-1981."

> "**a minister was reported to have paid a handsome ranson to free himself from the cultches of the dreaded dacoit chief Chhaviram.'

MR. DEPUTY SPEAKER: You should not mention the name of the Minister.

SHRI E. BALANANDAN: I am only reading.

MR. DEPUTY SPEAKER: No; even if you are reading you cannot. (*Interruptions*) I will not allow.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: I will not allow. I will go through the records and expunge it. You can say, "The Minister", but you cannot mention the name. He is not here to defend himself. (*Interruptions*). I will not allow. It is not a public document. I will not allow the mention of the name.

SHRI E. BALANANDAN: His name is deleted. I would only say 'The Minister'.

> "*Blitz*' continues: "Against the original ransom demand of Rs. 2 lakhs made by Chhaviram through the Minister's PA, a compromise for Rs. 1 lakh was reached and the amount was paid to the dacoit chief, it was learnt. Chhaviram was understood to have threatened to kidnap the Minister and his family if the ransom was not paid.."

This is not only the position. We have heard about Deoli, Sadanpur and Kistar also where these dacoits have attacked and killed people. Then we have heard about the bank robbery in Delhi. Then we have also heard about robbery in the trains. In Delhi, I must say, people feel unsafe, because on any day, these dacoits can come and do anything they like. I don't say that everything is O.K. in West Bengal: Some trouble will also be there.

**Expunged as ordered by the Chair.

[Shri E. Balanandan]

But in India what is the main problem today? The serious problem is that in large parts of the country the political leaders are in league with these dacoits.

In the President's Address, they have mentioned about the working class. The Central Government is the biggest employer of the workers. They should be an ideal employers. I now want to draw your attention to the agreement with the workers. Workers wanted them to implement that agreement, but they did not implement it. There was a contract between the LIC management and the workers. That was also not implemented. The workers went on agitating about it. The Government thought that it was a wrong agitation and therefore, they had imposed certain changes unilaterally in that agreement which was in force. Then the workers had to join together and to agitate about it. After that, a national campaign committee was set up. I do not want to elaborate on it. There was a meeting held in Delhi in which 10 lakh workers came and told the government to change their attitude towards the working class. But the Government had declared the one day protest strike as illegal. In a democratic set up. If the workers go on strike for one day, is it such a big thing? But the Government had arrested 50,000 workers one day before the strike. I have got a circular sent by th Bharat Coking Coal Ltd. to its subsidiaries asking them to take steps against the workers. Their one day's wages should be cut and the police should be informed about the people who are to be arrested. It is a secret circular sent to all their subsidiaries.

Then it has been mentioned in the President's Address that the production has increased; it has been increasing. Who increases the production? It is those workers who increase the production and not we people who are sitting in the Parliament. It is the workers who are working in the public sector industry, they are increasing the production; it is the agricultural workers who are increasing the production. The workers are contributing their mite for improving the production. But the Government is rewarding them with the following things.

The Central Government have declared 16 services as essential services. Under NSA, these workers can be taken to task. That is the reward that the Government is giving. Another contribution which the Government has made is that the Central Government Employees' arrears with regard to D.A. and CCA etc. have been impounded.

MR. DEPUTY SPEAKER: I think the Government has not taken any decision.

SHRI E. BALANANDAN: I hope I will stand by you. Then the real wages of the workers, of the Central Government Employees have been eroded from 7 per cent to 46 per cent from 1971 to 1981, according to the Government of India's statistics. The real wages of the public sector employees have come down to 18.3 per cent. The real wages of the factory workers have come down to 10 per cent and the real wages of the agricultural workers have also come down to 40 per cent during the last 10 years. On the one hand, the real wages of these workers have come down; on the other hand, they are increasing the production. The Government of India is the biggest employer. They should implement their agreement with the employees that they will raise their salary when the cost of living index goes above a certain point. There was an agreement between the Central Govrnment and the employees that when the cost of living index goes over 272 point, the wages of the Central Government Employees will be revised. Are they implementing this agreement? No,

they are not doing it. They tell the workers to produce and perish. That is the solution.

I am asking my hon. friend Prof. Ranga whether he supports this kind of attitude on the part of the Central Government with regard to the agreement which was in force and which should and ought to be implemented by the Government of India. On the one hand, the real wages of the workers are going down and down; while they are contributing more and more towards increasing production in the country and for which they are being penalised.

What is the other side of the picture? The Finance Minister was finding fault by saying that the communists were always talking about monopoly capital. I do not want to quarrel with him now. I want to bring to his notice that the real wages of the employees, the agricultural workers and the workers of the public sector undertakings are going down. The total assets of the 20 topmost monopoly houses stood at Rs. 3071.98 crores in 1972 and they jumped to Rs. 6615.69 crores in 1979. The profit of these 114 companies before tax stood at Rs. 712.5 crores in 1978 and it jumped upto Rs. 976 crores in 1979. This trend is kept up.

The point is that the workers are producing which is being cornered by these people and the workers are not given their dues. This is the line which you have adopted. We produce; we die and you take away and enjoy.

MR. DEPUTY SPEAKER: No politician produces anything.

SHRI E. BALANANDAN: That kind of theory would not stand. I am a worker. The State Government of Bihar had issued an order, shoot at sight order, to the police saying that if any worker goes and obstructs any other loyal worker, the should be shot at sight! Who is to be shot at sight? A worker who wants to ask his co-worker not to go to work has to be shot at. That is the punishment offered by the Government of Bihar. To shoot at sight! Is it democracy? I am asking. The worker has a right to picket.

In London, I can tell you, friends, a worker can picket and go on strike. You are supposed to get everything from London. A worker in London can do that. This is the line you have taken in India. I can tell you. Thousands of workers have been penalised. In a single factory in Haryana, the Haafeed Spinning Mills, where the total number of workers is 1,400 all the 1,400 workers were dismissed.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Not in Poland? (*Interruptions*)

SHRI E. BALANANDAN: You defend Poland separately.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why should you defend Poland?

SHRI E. BALANANDAN: Another factory in Haryana Concast Limited, has dimissed all the 400 workers! I do not want to repeat all the lists I have with me. In Posts and Telegraphs, Railways and in all departments. if a worker absents from duty, his salary is cut and his wages are cut, even if he went on one day's leave on the 19th Janutry, 1982.

Now, I am asking you, about the Central Government employees. The promise you have given to them, the contract why you are not implementing. I am again coming to one of the very important points. That is the point about corruption. Corruption, what should I say.? The President as I referred to earlier, in his Republic Day speech referred about values and morals. Here, in this House we had, last time,.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think you have taken both the speeches togethtr. President's address and the Republic Day speech.

SHRI E. BALANANDAN: Yes, both are President's speeches. The President is President. Can you belittle him? (*Interruptions*) The point here is, during the last session this august House had the occasion to understand a Chief Minister, the great Chief Minister, one time Chief Minister, Mr. Antulay. We know him. I do not want to put his name here, Antulay, with the trusts to his credit, seven or six trusts he had, to his credit; he had the molasses contract to his credit, the cement disposal he has to his credit, No-Objection Certificates, and so on and so forth, with a capital of Rs. 30 crores in trusts alone, legally. I do not know the rest.

Now, another **has taken to the scene. That is my friend Gundu Rao. (*Interruptions*) All right, I do not want to say.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not mention. The word used by him is unparliamentary. I am expunging it directly. He is an hon'ble Chief Minister.

Now, I am referring to the *Times of India* editorial dated February 20th. "Cement Again" is the heading. Since the Cement is big business industry in the Country, I quote from *Times of India*—

> "Cement Again: The Public Accounts Committee of the Karnataka Legislature has not minced words in criticising the State Government for diverting 4,000 tonnes of cement to private contractors to put up high-rise buildings in Bangalore. The Centre had made a special allotment of 10,000 tonnes of cement to the State for Power and Irrigation projects. The PAC calls the diversion" a case of undue favouritism and misuse of authority, and has "felt constrained to observe that the maxim of *quid pro quo* must be the test for distribution of cement in this manner."

The Maharashtra High Court said the very same thing about Shri Antulay, who is not a Chief Minister now. And Karnataka PAC unanimously said this. The Karnataka State is ruled by the Congress (I) Party. And the Public Accounts Committee says this thing against the Chief Minister. That is the mettle of one Chief Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will have to conclude. You have already taken 40 minutes.

SHRI E. BALANANDAN: There is an article written by Shri Kuldip Nayyar in '*The Tribune*' about Mrs. Gandhi's Chief Ministers. The heading of the article is 'Between the Lines'.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not mention names.

SHRI E. BALANANDAN: The name of the Gujarat Chief Minister is there. The name of the Madhya Pradesh Chief Minister is there. The name of the Bihar Chief Minister is there. All these Chief Ministers except two in India are mentioned in this article by Shri Kuldip Nayyar.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Who are the Chief Ministers he has not mentioned?

SHRI E. BALANANDAN: Andhra and some other State. The Congress (I) people are raising objections and levelling allegations. So, I am only submitting here about corruption that there is a Congress (I) culture. You may know it. It is a corruption culture: Who is protecting them? Last time, Prof. Dandavate put it forcefully about that Maharashtra man.

PROF. MADHU DANDAVATE: He can refer to me because I am in the House.

SHRI E. BALANANDAN: The Prime Minister came to defend him.

**Expunged as ordered by the Chair.

That is the Congress (I) culture, which is a corrupt culture. If Chief Ministers behave in this manner, others would follow suit. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must conclude.

SHRI E. BALANANDAN: If somebody who does not have any understanding about a mirror, sees his ugly face in the mirror, he will bang the mirror and break it. That way, Shrimati Indira Gandhi was saying the other day that the national Press in the country is for the opposition. They are bringing out what is going on in this country. Press is the fourth estate in the democracy. The fourth estate in a democracy is the guardian of democracy. It protects the interests of the country. If you attack the fourth estate, because it is bringing out things which are not palatable to you, it is not proper. It may bring out something which she may not like, somthing else also which I may not like. That does not mean that we should attack the fourth estate. Yet, our Prime Minister says that the fourth estate is a threat to democracy.

I do not want to go into the financial claims made by the Government of India. I will refer only to one or two small things.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can deal with them in the budget.

SHRI E. BALANANDAN: They have suggested one remedy for all the economic ills, and that is the 20 Point Programme. I will not deal with all the 20 points, but I will certainly deal with two of them. One is the distribution of land. The Planning Commission says that by this year 1982 all the available surplus land will be distributed to the needy people; that is the line taken by the Sixth Plan. Yet, the 20-Point Programme says that the surplus land will be distributed to the landless by 1985. So, the question is whether it is 1982 or 1985.

Another claim relates to formal education. The Sixth Plan says that 80 lakhs of people have to be educated. But the 20-Point Programme has reduced it to 30 lakhs. I do not want to go into the story of the earlier 20-Point Programme. I say that they are all meant to hoodwink the people. Even the present Programme is going back from the Sixth Plan; it will not take the country forward.

A claim is made that production has increased. In the last budget session the Parliament took a decision to legalise 25 per cent of the excess capacity of plants. It is obvious that before this decision was taken they were working beyond the permitted capacity illegally. Now that it has been legalised, they will show it in the accounts. That is the only difference. Now in the accounts also the production will go up. That is the only difference, notwithstanding their claims to increased production.

I will leave it to my colleague to deal with the economic policy. I now come to our foreign policy, many aspects of which we support. The President says:

> "The international situation has deteriorated. Military presences around us have increased. This danger should make all of us determined to safeguard national security and interests through non-alignment and the peaceful resolution of differences. We earnestly hope that the major military powers will realise the futility of confrontation...."

16.00 hrs.

[Shri Harinatha Misra in the Chair]

All right. That is some kind of hesitancy. What is it that the 'major' military powers will realise? Who are the major military powers? Who

[Shri E. Balanandan]

are creating troubles for us? You will find that in Diego Garcia there is one lakh rapid deployment force and there the most modern atomic weapons are kept by America. It is claimed that Pakistan is being armed to fight Russia. Who will believe that? Can Pakistan fight Russia? No. One can build up that kind of a theory, and somebody is enomoured of democracy saying that democrats in America want to protect Afghanistan and democrats in America want democracy in Vietnam and they will now protect democracy in El Salvador and African countries. All this is bunkum. I must say that all kinds of arguments have been put forward to show that American imperialists support democracy anywhere in the world. No. They are imperialists. Some friends the other day were talking about freedom. We fought imperialists and we got freedom. Very good. The balance of power has been shifted after the Second World War. That is the ABC of politics. The Second World War brought into the world a force which says that imperialism must go and that was one of the basis for us to fight freedom and get freedom. That was the working class movement and the Communist Party. and that was the guarantee for getting freedom for the countries of the Third World. Therefore, we are somewhat in agreement with Shrimati Indira Gandhi with regard to foreign affairs. But you must call a spade a spade. That much strength should be there. In the debate somebody may differ. That is all right, one can understand it. But you have to see that in the American budget the military expenditure is doubled and the totality of their technological efficiency is being diverted and utilised for arms build up. Arms build up of what type? For Bacterial war, atomic war and the so-called hydrogen bomb etc? Bombs are thrown on the other people saying that war danger is coming against them from elsewhere. In Western Europe they art saying, 'All right, you keep these bombs here to fight the Soviet Union. That way the American imperialism is selling these war materials and making profit. They want to pressurise India to accept their line in internal policy and external policy.

Somebody was talking about people's unity. The whole truth should be told to the people. Then only you can mobilise the people. That way I am disappointed.

All these points have not been mentioned by the President in his speech, and my dear friend Rangaji was requesting me to support his Motion of Thanks. How can I support this motion? I can only oppose it and oppose it vehemently.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, मैं इस माननीय सदन में सरकार की भूमिका के साथ-साथ विरोधी दलों की भूमिका को बड़े गौर से देखता रहा हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि विरोधी दल के लोगों में जो गर्मी पहले थी, जो उत्तेजना उन के अन्दर पहले थी, जो क्रोध उन के अन्दर पहले था, जो पीड़ा वह पहले दिखलाते थे, उसमें पिछले दो सालों में धीरे-धीरे बराबर कमी आती गई है। इस से दो भी नतीजे निकल सकते हैं। या तो देश में इसूज नहीं हैं, समस्याएं नहीं हैं या विरोधी दल के लोगों की क्षमता में कमी आ गई है। मैं तो यह नहीं मान सकता कि विरोधी दलों के लोगों की क्षमता में कमी आ गई है। बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, अर्थ-शास्त्री हैं, राजनीति के ज्ञाता हैं, प्रशासक रहे हैं और सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनकी क्षमता में कमी नहीं आ सकती लेकिन सरकार का सब से बड़ा एचीवमेंट यह है कि पिछले दो वर्षों में उनको इसूज नहीं मिल रहे हैं, उनको समस्याएं नहीं मिल रही हैं, सरकार को मारने के लिए उनको छड़ी नहीं मिल रही है। एक घटना यहां हो गई, एक

घटना वहां हो गई, एक घटना किसी दूसरी जगह हो गई, प्रत्येक समय उसी का उल्लेख करना है, उसी बात को दोहराते रहना है। बात यह है कि उन के पास इशूज नहीं हैं और वे हर आवर को जीरो-आवर की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं और कोई काम की बात उन्होंने नहीं की। मुझे आशा थी कि विरोधी दलों के लोगों की तरफ से देश के चलाने के मामले में रचनात्मक सुझाव आएंगे, तर्कपूर्ण सुझाव आएगे और ऐसे सुझाव आएंगे, जिन से सरकार को चलाने में मदद मिलेगी।

विरोधी दलों के पिछले दो वक्ताओं की, दो नेताओं की बात मैंने सुनी थी लेकिन उस में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अभी श्री बालानन्दन जी एक बात कह रहे थे कि सरकार इस सदन को, संसद् को बाई-पास कर रही है। सरकार संसद् को बाई-पास नहीं कर रही है क्योंकि वगैर पार्लियामेंट को विश्वास में लिए सरकार का काम नहीं चल सकता लेकिन मैं बड़े अदब के साथ विरोधी दलों के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल संसद् को बाई-पास कर रहा है। क्या बात है कि आज विरोधी दलों के स्टालवर्ट्स, बड़े-बड़े नेताओं की बात इस संसद में सुनने को नहीं मिलती। हम उनकी बात सुन नहीं पाते हैं। वे संसद् के सदस्य हैं, वे कुछ रचनात्मक सुझाव नहीं देते, सरकार को देते, जिससे हम भी उनसे कुछ सीख सकते और देश की गाड़ी भी आगे चलती लेकिन वे लोग तो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। संसद के समक्ष बात करना उन्हें पसन्द नहीं। वे पर्दे के पीछे केवल इसी बात में लगे हुये हैं कि कौन-सा जोड़ तोड़ किया जाय, कौन सी तिकड़म लगाई जाये जिससे इस सरकार को गिराया जा सके गलत तरीके से या फिर चुनाव को जीता जा सके और सरकार अपनी बनाई जा सके। इस तरह से संसद में जो विरोधी दल के नेता हैं, बड़े-बड़े स्टालवर्टस हैं, वे संसद को बाई-पास कर रहे हैं और उनकी बातें संसद् के सामने नहीं आ पाती और संसद के माध्यम से उन की बातें देश के सामने नहीं आती... (व्यवधान)... बहुत से लोग यहां आये हुये हैं लेकिन वे पर्दे के पीछे काम करना चाहते हैं और संसद में आ कर काम नही करना चाहते। इस तरह से वे लोग खुद संसद को बाई-पास कर रहे हैं। हमारी सरकार के लोक संसद को बाई-पास करके एक दिन भी चल नहीं सकते, संसद को विश्वास में लिये बिना उनका काम आगे नहीं बढ़ सकता है।

पीछे ढाई वर्षों तक विरोधी दलों के कुछ लोगों ने ही नहीं बल्कि अधिकतर लोगों ने शासन किया। वे इधर आ गये थे और जनता ने हमें उधर कर दिया था। उन ढाई वर्षों में उन्होंने देश के सामने क्या आदर्श प्रस्तुत किये? कौन सा आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको कि हम माने, जिसके लिये कि हम काम करें, जिससे कि हम सबक सीखें?

उनके शासन में आने के बाद ऐसा लगता था कि उनका केवल एक ही मंशा है कि किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी की चरित्र हत्या कर दी जाये, किस तरह से उनको जेल भेज दिया जाये, उनको परेशान किया जाये, उनको तंग किया जाये, उनको राजनीतिक रूप से समाप्त कर दिया जाय, बर्बाद कर दिया जाये। यह उनका वन प्वाइंट प्रोग्राम एक सूत्री कार्यक्रम था जिस पर कि उन्हों ने अमल किया।

दूसरे उन्होंने शासन में आने के बाद विधि के अधीन चुनी गयी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया और यह कहकर कर दिया कि संसद् में एक नयी पार्टी का बहुमत होने के कारण राज्य सरकारों ने जनता का विश्वास खो दिया। यह एक नयी बात उन्होंने की और आरबीटरेरी तरीके से, गलत

[श्री जैनुल बशर]

तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ कर सारी राज्य सरकारों को भंग कर दिया। दूसरा आदर्श उन्होंने यह प्रस्तुत किया।

आज ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस हाई कमान दिल्ली से मुख्य मंत्री को मनोनीत करता है। राज्यों के विधायकों को इस बात की इजाजत नहीं दी जाती कि वे अपना नेता स्वयं चुन सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया ? क्या चौधरी साहब ने या वाजपेयी जी ने यहां से मुख्य मंत्रियों को मनोनीत करके राज्यों में नहीं भेजा ? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में यहां से मुख्य मंत्री मनोनीत हो कर नहीं गये ? एक यह आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया।

एक और आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें। उस समय के गृह मंत्री यह कहते हैं कि सरकार में भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं। दुनिया के इतिहास में शायद यह पहली घटना होगी कि किसी सरकार का गृह मंत्री यह कहे कि उसकी सरकार में अधिकांश मंत्री लोग गलत है, भ्रष्ट हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि सरकार के दो-एक मंत्री बाहरी देशों के जासूस हैं, के०जी० बी० के जासूस हैं और दूसरी विदेशी एजेंसियों के जासूस हैं।

इस तरह से वे आपस में बराबर लड़ते और झगड़ते रहे और इसी लड़ाई-झगड़े में सरकार का काम चौपट हो गया। यह लड़ाई झगड़ा यहीं तक नहीं रहा। यह राज्यों तक में पहुंचा, जिलों तक में पहुंचा और वहां भी सारा काम ठप्प हो गया। यही कारण था कि सरकार पांच साल तक नहीं चला सके और ढाई साल में ही अपने बोझ से दब कर उनकी सरकार ने दम तोड़ दिया। यह सारा काम उन्होंने किया।

सभापति महोदय : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इसी वजह से वे उधर चले गये ?

श्री जैनुल बशर : सभापति जी, हम यह कहना चाहते हैं कि जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया उसी को कसौटी मान कर ये हमको परखना चाहते हैं। क्या वे यह चाहते ह कि जिस रास्ते पर वे चले उसी रास्ते पर हम भी चलें ? क्या वे अपने क्रिया-कलापों के पैमाने से हमको भी नापना चाहते हैं ?

माननीय सभापति जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने एक आदर्श स्थापित किया है। इस देश में हमारा अपना एक तरीका है। हमारा वह तरीका है जिसे इस देश में महात्मा गांधी, ने, पंडित जवहर लाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी परम्पराओं से स्थापित किया है, उसी पर हम चलना चाहते हैं।

सभापति जी, सब से बड़ी उपलब्धि हमारी यह है कि हमने एक राजनीतिक स्थिरता इस देश में कायम की है। राजनीतिक स्थिरता कायम होने से आर्थिक स्थिरता कायम हुई है। पिछले ढाई वर्षों में जो राजनीतिक स्थिरता या आर्थिक स्थिरता की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी, इस सरकार ने उस गाड़ी को फिर से पटरी पर ला दिया है और वह गाड़ी चल दी है—गाड़ी चलने लगी है। यह सरकार की कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दो वर्षों में यह गाड़ी चल निकली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले तीन वर्षों में यह गाड़ी तेजी के साथ चलने लगेगी और जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किये हैं, जिस बीस सूत्रीय कार्यक्रम की अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की, उसको अपनाते हुये हम आगे बढ़ते जायेंगे और देश की प्रगति होगी।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति द्वारा यह अपील की है कि विरोधी दल के लोग सहयोग करें। यह कोई हमारा मामला नहीं है,

हम तो पांच साल के लिये चुनकर आये हैं। हमारे अन्दर कोई फूट पड़ने वाली नहीं है। जनता पार्टी का आदेश हमारे सामने नहीं है। हम पूरे पांच साल तक शासन करेंगे। विरोधी दल के लोगों के पर्दे के पीछे के कार्य-कलाप हमको कुर्सी से नही हटा सकते। यह बात आपको समझ लेनी चाहिये। उनसे किस बात के लिये सहयोग मांगा जा रहा है? हम अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए यह सहयोग नहीं मांग रहे हैं। कुर्सी से वे हमको नहीं हटा सकते। हम उनसे सहयोग मांग रहे हैं इस देश में काम करने के लिये।... (व्यवधान)... इंदिरा गांधी को बचाने के लिये हम आपसे सहयोग नहीं मांग रहे हैं, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम केवल आपसे सहयोग मांग रहे हैं इस देश को चलाने के लिये। इस देश में आर्थिक प्रगति के लिये, इस देश को आगे बढ़ाने के लिये—इन कामों के लिये आपसे सहयोग मांग रहे हैं। जब-जब आपने सहयोग दिया, हमने सहर्ष स्वीकार किया है। आसाम के मामले में आप ने सहयोग देने की बात कही थी, आसाम के मामले में आपने सहयोग दिया, क्या इस बात से आप इंकार कर सकते हैं कि सरकार ने आप से सहयोग नहीं लिया? क्या सरकार ने आपको आसाम की बातचीत में शामिल नहीं किया? मुझे पूरी आशा है कि इसी प्रकार देश की अन्य समस्याओं के बारे में यदि आप रचनात्मक सहयोग देने की पेशकश करेंगे तो सरकार उसे अवश्य कबूल करेगी और आपकी रचनात्मक बातों को मानने के लिये हमेशा तैयार रहेगी इस सहयोग की बात हम कर रहे हैं। देश को चलाने की बात हम कर रहे हैं। आप रचनात्मक सुझाव दीजिये।

सरकार तो तभी बदल सकती है जब जनता आने वाले चुनाव में उसको वोट न दे। आप कांस्ट्रेक्टिव बात कीजिये, जनता को समझाईये कि जो तरक्की होनी चाहिये, वह हम नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिये, और भी बोलने वाले हैं?

श्री जैनुल बशर : बस पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। सभापति जी, इन बातों के साथ साथ मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार प्रगति के काम कर रही है और जैसा कि मैंने कहा है कि गाड़ी चल निकली है, लेकिन जितनी तेजी के साथ गाड़ी चलनी चाहिये थी, उतनी तेजी के साथ नहीं चल रही है। इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर नहीं किया जायगा, तब तक पूरा देश खुशहाल नहीं होगा। सभापति जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश की आजादी के दिनों में दो क्षेत्र सबसे आगे-आगे थे। जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी थीं और काफी बलिदान दिया था। जिसके कारण अंग्रेजों ने उनको पीछे रखा था आज भी उनकी तरफ ध्यान नही दिया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ऐसे स्थान हैं जिन को पीछे रखा गया था और आज भी वे पीछे हैं। पिछले दिनों अखबारों में पढ़कर मुझे खुशी हुई थी कि चौराचौरी में प्रधान मंत्री ने शहीदों के स्मारक का उदघाटन करते हुये कहा था कि अब सरकार उन क्षेत्रों और उन जिलों की तरफ ज्यादा ध्यान देगी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वहां उद्योग धंधें खोले जायेंगे, वहां विकास कार्य किये जायेंगे। प्रधान मंत्री की इस बात का मैं स्वागत करता हूं। मैं भी एक ऐसे जिले से आता हूं—जिसने आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, सब से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 से लेकर 1947 तक वहां के लोग आजादी के लिये बराबर झूझते रहे हैं, आजादी के लिये कुर्बानियां बराबर देते रहे हैं। इसी कारण से अंग्रेजों ने उसे जिले को बराबर पीछे रखा।

[श्री जैनुल बशर]

उसके साथ साथ उन्होंने अन्य जिलों को जो उसके साथ लगते थे पीछे रखा और वहां कोई तरक्की के काम नहीं किये। यह सही है कि आजादी के बाद अब तक काफी प्रगति के काम वहां हुये हैं लेकिन जैसी उन लोगों की आकांक्षा है, जैसा वे चाहते हैं, वैसी प्रगति नही हुई है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री के आश्वासन के बाद वहां प्रगति की रफ्तार में तेजी लाई जायेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश में साम्प्रदायिकता पर काबू पाया जाना चाहिये, साम्प्रदायिकता देश में घुन की तरह लग सकती है। अगर यह घुन लग गया तो अंदर-अंदर हम खोखले हो जायेंगे। हरिजन स्वर्ण का मामला हो, एक जाति और दूसरी जाति का मामला हो, एक धर्म और दूसरे धर्म का मामला हो, मैं चाहता हूं कि इन सब मामलों में सख्ती बरती जानी चाहिये और जो लोग दूसरे लोगों को सताने का काम करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिये, इस चीज को समाप्त किया जाना चाहिये। इस संबंध में अभी हाल ही में विराट विश्व हिन्दू सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था उसको हिन्दुस्तान में अब जगह जगह आयोजित किया जा रहा है और एक जहर फैलाया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है कि हिन्दू धर्म खतरे में हैं। समझ में नहीं आता कि जब इस देश पर सैंकड़ों साल मुसलमानों ने शासन किया, हिन्दू जब शासित थे, शासक नहीं, तब तो हिन्दू धर्म खतरे में नहीं पड़ा लेकिन अब हिन्दू धर्म किस तरह से खतरे में पड़ गया है? तब तो हिन्दू धर्म जीता जागता रहा लेकिन आज इस युग में, एक जनतांत्रिक परम्परा में जहां इस देश में अस्सी प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दू हैं हिन्दू धर्म कैसे खतरे में पड़ गया है। यह बात मेरे समझ में नहीं आई है। वाजपेयी जी हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद उनकी समझ में यह बात आती हो लेकिन मेरी समझ में तो आती नहीं है। अस्सी प्रतिशत जिनकी इस देश में आबादी है, उस धर्म को कैसे खतरा पैदा हो सकता है, वह कैसे समाप्त हो सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। आप देखें कि अंग्रेजों, मुगलों, मुसलमानों के—जमाने में भी हिन्दू धर्म समाप्त नहीं हुआ था तो अब कैसे हो सकता है। ऐसे कार्य-कलापों को रोका जाना चाहिये। म गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं —जो इस वक्त यहां नहीं हैं—कि उनके कार्यकलापों पर विशेष नजर रखी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका स्वागत करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI (Banaskantha): Mr. Chairman Sir, I rise to support the motion moved by our deputy leader, Prof. Ranga.

Two years ago, when we went to the polls, a short promise but a very important promise was given to the people, "Please elect a Government that works". I am very happy to find from the President's Address that it not only outlines the future policies of the Government but it furnishes some account of the past with figures and facts. From the figures and facts, you and the entire House would be pleased to appreciate that out of the things which had almost gone out of hands, so much has been retrieved and again the country has been put back on the proper rails as well as on the path of consolidation not only in the sphere of economy but also in the sphere of political stability as well as in the sphere of international prestige and image of our country and, it is the proof that this Govt. works. I was surprised that when President was going to tell us about our achievements, about our policies as to what in future we are going to do, at that time, it was very sad, it was

very unfortunate, that some people in the Opposite side, took it to their mind to boycott that Address. Is it the way to be conducive to furthering the cause of democracy? The explanation that they gave was, that we wanted to respect the President and, therefore, we remained absent from his Address." If this is the way in which they are thinking about saving democracy, keeping the traditions alive of democracy, then, I am afraid with whatever rhetorics, whatever high-sounding words they may be telling us about preservation of the democratic traditions, they cannot help safeguard, they cannot help upkeep the democracy in this country.

Yesterday I was very patiently hearing Mr. Ram Jethmalani. He was putting forth certain conditions about extending cooperation to the Government. And one of the conditions that he mentioned was that there should not be a personality cult and sycophancy. Let me reply although he is not present in this House, that Congress people and we, we do not indulge in the sycophancy and personality cult but, we have got reverence for Mrs. Gandhi and we will continue to have it. We have all the while reverence for not all the leaders but only Mrs. Gandhi who were the all saviours of this country who took the country to the right path. If that is construed, if that is termed, as sycophancy, then, I humbly say on behalf of my Party that we refuse that condition. Even if the cooperation is coming forth with that condition, then, we do not want that cooperation. We are not afraid. What is the cooperation that was asked by our Deputy Leader. What was the cooperation? We wanted cooperation because we wanted that in this country where secularism has been threatened. in this country where the integrity of the country has been threatened. A uniform force should be evolved which can combat those forces. Today what is happening? We have heard about Sholapur and Pune. We have heard about the communal riots elsewhere and we know that for petty selfish motives, parochialism and religious fanaticism is being fanned even when the nation is marching towards progress. There are elements, only with a view to have their selfishness satisfiled, they incite those people. I may give an example. We have got a family welfare programme, which is a national programme. I am afraid I have witnessed it myself in my district. We were organising a very big family welfare camp where the family operations were to be done and, for your knowledge, Mr. Vajpayee, although I believe that your Party would not be there, but your own workers who are in the villages, perhaps you do not know, they travelled in jeeps and in trucks, all throughout the villages, exhorting the people, even the Muslims, not to go for family welfare camps. If this is the approach, if this is how we want to fight the dangers against our nation, then, can you really believe that we can fight them out? Can you really imagine that you and we can contribute our share in solving the problems of this nation and, if not so, then, whatever may be our high talks about the upkeep of democracy. the preservation of democracy, I think, they would always remain there and that would not come to the material and concrete facts.

Mr. Jethmalani was telling about the presidential and democratic setup, the presidential form of Government. Who is talking about that? Nobody talks. Indiraji has all the while declared that this democratic institution which we have got today, the parliamentary system of Government, there is no idea even, about disturbing it. It is merely the creation of some of the so-called intelligentsia of the society. They indulge, they like, they wallow in the realm of their own enjoyment of twisting and travesting the facts and then, our Press highlights it. Today, every opposition wants to exploit situation, of course, any situation that is beneficial to them for exploitation. Take the case of Harijans and Adivasis. Wherever there is atrocity on Harijans or the

[Shri Bheravadan K. Gadhavi.]

downtroddens, we hear a lot of hue and cry from the Opposite side. I want to ask a simple question to this House that whether Gandhiji was a man dedicated to the cause of Harijans or not and if the answer is 'yes', then, please answer me that who are the persons responsible who went to the statue of Gandhiji and smeared his forehead with the tilak of blood? They belong to what cadre? Please make an introspection and find out whether the lip-sympathy which you are telling today, which you are expressing today, is proper or whether the real sympathy is there in the revised 20-Point Programme, there is a special mention about Harijans and Adivasis' welfare. Why? Because Mrs. Gandhi is dedicated for their well-being.

AN HON. MEMBER: Whose duty it is to protect them?

SHRI BHERAVADAN K. GANDHAVI: It is the duty of the whole nation. It is the duty of the entire nation. It is not only our duty. But if a few persons who are religious fanatics, they could smear the forehead of Gandhiji even with blood, then they can do anything in this country and to fight those forces, even if we have to lay down our lives, we don't mind it It is not only your monopoly. Mr. Balanandan talks in terms of workers. It is not your monopoly to talk in terms of workers. Agricultural production has increased. He cannot controvert it. Industrial production has increased. He cannot controvert it. Who has increased? The labourers and the peasants of this country. And why? Because they found it more favourable, congenial atmosphere in the present regime than the atmosphere that was in yours. In your regime, what was the atmosphere? The growth was negative. And today you compare it with figures of Industrial production, agricutural production, infra-structure, coal, electricity, fertilisers and so many other things. You cannot controvert those figures and you cannot controvert that the labourers and peasants are put in the most congenial conditions only during the regime of this Government and, therefore, this Government enjoys the support of the people. So many people talk about democracy and this and that in the past. I do not want to say much about past. In the past, what you did. You reaped what the deeds deserved. In order to preserve democracy and maintain the democracy in this country, a sense of introspection is also required and you should examine the inner recesses of your heart and find out whether the present behaviour is proper? What was that call for Bandh on the 19th which flopped.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: It was not a flop.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: We say it flopped. Don't you think it, Shastriji, that when the clouds are hovering around the horizons of this country, don't you think it proper that when the clouds of war are gathering on the horizons of this country, the production of this country should go up ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Before telling us this thing, Can you tell us why you require ESMA and NSA ? What is the necessity ?

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI : If you want to preserve democracy, then democracy cannot be preserved without dedication; if you want to preserve democracy, then democracy cannot be preserved without discipline; if you want to preserve democracy, then democracy cannot be preserved without devotion to the country and to duty..(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Let him have his say.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI : It is very difficult for them to swallow the truth..(*Interruptions*)

श्री रामावतार शास्त्री : हमारे वर्करों पर हमला किया गया, उनके सिर फोड़े गये ।

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI : He is a very senior Member; he knows where the shoe pinches. I have great reverence for him.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Does the ruling Party want us to be as dedicated as Mr. Gundu Rao and Mr. Antulay ?

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI : I am not concerned with State Governments.

MR. CHAIRMAN : Mr. Chakraborty, would you like to be disturbed like this when you are speaking ? Let him have his say.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI : I know, the call for bandh on the 19th was a flop.

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, आप जानते हैं कि उस दिन कितनी शानदार हड़ताल हुई । माननीय सदस्य उसको "फ्लाप" कह रहे हैं ।

सभापति महोदय : आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा । माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए । आप कहते हैं कि आप बहुत सफल रहे । माननीय सदस्य का कहना है कि आपको सफलता नहीं मिली ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, के क्षेत्र में तो हड़ताल नाकामयाब रही ।

श्री रामावतार शास्त्री : पटना में इतनी शानदार हड़ताल हुई कि जैसी पहले कभी नहीं हुई थी । वहां पर मंत्रियों ने, डिपुटी मिनिस्टरों ने, एल आई सी की बिल्डिंग में घुस कर लोगों को पीटा । अगर आप कहें, तो मैं उनके नाम बता दूं ।

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI : Why should he got excited ? I want to tell them one thing. A *sine qua non* for democracy is to have the capacity for patience. Unfortunately it is lacking there. That was the reason why you all went away to that side. You should have the capacity to listen to truths. What I was submitting was....

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You are now sermonising about patience. What did you do when Mr. Balanandan was speaking?

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: Was he disturbed? (*Interruptions*) Today they are afraid of listening to the true facts because they know that not only this nation but even the other countries recognise this; in New Delhi there are consultations today among 44 countries spearheaded by India, and the entire developing nations of the world look forward to India for guidance. Why? Because they know that a leader like Mrs. Indira Gandhi can show them the right path of progress. And that is what my friends there do not like. (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : The saviour of mankind cannot save India!

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: Our respected Mr. Vajpayee had to return immediately from China; we know all that. But that is a mattar of the past. We cannot build anything new only by considering the past events and criticising them. Today on all fronts when we want to bring tranquillity peace, among the various communities and developments all around, at that very time, I want to know whether there is any contribution from the Opposition side.

[Shri Bheravadan K. Gadhavi]

If there is no contribution from you and, in fact, if somebody asks you to please contribute not for my sake, not for personal ends but for the purpose of the progress of the nation, then we may say that the nation advances. Don't go through the personalities. If they do not do anything, then we may suffer. We must know the broader perspective, the broader idea, as to where we want to go under the present circumstances. There are difficulties, of course. You all talked about the common man. Why there should be double standards on your part?

We know that in the cities you tell the people that the sugar price has gone up so much but in the villages your stance is quite different. Let me now tell you that the people have understood you. They know what is going on inside and outside. Therefore, it would be better for you to let go your double standards. So long as you indulge in this sort of thing, I am afraid, despite all the lip sympathies that you may show to the working-class and the peasants, they would not come closer to you.

Always the tradition of the Congress is to help them. You were talking about the farmers since two years or so. A bank was awaited so long--NABARD. Before Independence there was a demand for that type of the Bank. It was only established during the regime of Shrimati Indira Gandhi.

Yesterday when we discussed the Bill, somebody commented about the agricultural community and asked: how many new institutions were being created to help our farmers?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Everything started moving during the regime of this Government.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: Somebody said that everything started after she was born. This is a certainty and it is a historical fact. You cannot deny that. You may call it a sycophancy. But, it is a reverence to me and it is dear to my heart.

MR. CHAIRMAN: Now you may conclude.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: In sum total, I may summarise that the President's Address to this House is giving a true account of the past and is outlining the policy for the future, enumerating the achievements that were made.

For that they say—Shri Ram Jethmalani said—that it was a professional hazard that the President had to address under compulsion. That is, how I understood him.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Occupational hazard.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: Is it an occupational hazard to be President of India? Can you treat the President like that?

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE: It is derogatory.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: I did not say that. Mr. Vajpayee you are a very learned man. I admit that you are learned.

MR. CHAIRMAN: Please do not drag in the name of the President in the discussion.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: No, no. I am not referring to him. I referred to the speech of Mr. Ram Jethmalani which has gone on record.

MR. CHAIRMAN: It will lead to all sorts of discussion.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: In our democracy, the President is supposed to act on the advice of the Council of Ministers. That is our Constitution. If the President is doing that and if somebody criticises him because he is doing something as per the advice of the Council of Minister, he is wrong and, if that is the

idea of somebody else, then it is cutting at the very root of our democracy and our Constitution.

MR CHAIRMAN: Kindly conclude now.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: I won't take much time. I shall finish.

I support this motion which has been brought forward by Prof. Ranga and I also join myself in thanking the President for having addressed the joint session of both Houses of Parliament

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): Mr. Chairman, Sir, the President's Address should contain a faithful and truthful account of the year that had gone by on the performance of the Government. It is like a balance sheet of the performance of the Government in the year gone by. It should also contain a correct appraisal of the current situation in the country and it also should tell us about the measures that the Government proposes to take to meet the situation that is obtaining in India.

But I am afraid this President's Address contains a partial picture of the situation in the country.

MR. CHAIRMAN: Would you kindly listen? You may come nearer the mike particularly as that will help our reporters?

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA: Yes, Sir.

The Address also contains half truths regarding the achievements claimed by Government on the economic front. Therefore, I am unable to support the Motion of Thanks moved by Professor Ranga.

Firstly, I will take up the question of law and order. Government have referred to agitations engineered by sectional interests and also the atrocities committed on weaker sections like scheduled castes and scheduled tribes. But they have not said that there is a general deterioration in law and order situation. It does not contain any reference to the situation created in U.P. by dacoits which has resulted in massacre of hundreds of people. It does not contain any reference to a similar situation in Bihar. Mini chambal valleys are springing up in Balia, Bettea and Rohtas in addition to the areas which were under the operation of the dacoits. It does not contain any reference to that. It does not contain any reference to the Naxalite movement which is manifesting itself in violent methods in various parts of the country, namely, Punjab, Bihar, Andhra Pradesh, etc.

You are, aware, Sir, that these forces —the poorer sections—have been organised by various factions of the Naxalite groups and they are operating in Bihar, for instance, under the name of Marxist-Communist Centre, Aziz-ul-Haque group and Mishra group. They have created an atmosphere of terror and fear in the country-side. People are afraid of going out after dusk. People are afraid of even cultivating their lands. They demand minimum wages. Government have also told us that in the revised 20-Point programme they are going to take more effective measures for enforcing minimum wages but the minimum wages fixed under the Act are not acceptable to them. In many places they say that the minimum wages should be fixed by those people and not by Government. Then they tell the agriculturists that they should not cultivate some lands. They should leave them to them, with the result that out of sheer fear of confrontation or meeting with violent forces many lands are left fallow and a situation of fear and terror prevails.

Sir, Government claims that law and order situation has improved and, perhaps, that is why in the Address we do not find any mention to these activities. But when we visit the rural areas we find the people are terror stricken. Those whose relatives have been killed are afraid of even

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

telling the truth. Such is the situation but the Government has not made any mention of that. If we certainly mean business, mere social change in our outlook will not bring us any results, as Prof. Ranga advocated yesterday.

I think that the entire socio-economic scene has got to be changed. We expected that the hon. President will say something about the change and the transformation which are sought to be brought about in the socio-economic structure of our country, but nothing has been mentioned by the President in his Address. Unfortunately, for the last so many years since our Independence, no significant change has taken place.

Sir, in spite of the fact that we have made progress in various fields, the real fruits of development have not reached large sections of our people. They are still suffering from deprivation, from frustration and so on, which are manifesting themselves in various violent activities. And if there is no large scale revolt, it is because large sections of our people have monumental patience to undergo long sufferings.

I do feel that if nothing tangible is done to change the life-style of the affluent section, if they do not undergo the change, if they do not create the proper climate of austerity, the days are not far off when there will be a revolt against conspicuous consumption by the people in our country.

Land reforms should be implemented urgently and peremptorily. We should devise a proper machinery to enforce the Minimum Wages as fixed under the Act. During the lean season we should provide work to our unemployed and under-employed people in the rural areas.

The Janata Party has come in for a good deal of criticism. It has become almost a kind of policy on the part of the Ruling Party to criticise the Janata party quite often. By doing this, they perhaps think that they are projecting their own image to the people. Let me tell you what the Janata party has done.

It is the Janata party which had started the Food-for-work programme which was a great success.

Now, just because this Food-for-work programme was started by the Janata party it was stopped by the Congress (I) Party. They re-named it as 'Rural Reconstruction Programme'. Let me tell you what actually happened during the Janata Party regime.

The man-days created under this Food-for-work programme were 353 millions in 1978-79. It was 582 million man-days in 1979-80. This figure came down to only 326 millions in 1980-81 under the new name, Rural Reconstruction Programme.

We are told that the estimated employment during the current year would be a miserable figure of 15 million man-days. Is this not a shocking thing, Sir? Is it a great achievement on the basis of which they proceed to solve the law and order situation in the country?

Sir, the President has not said anything about the situation in the North-Eastern States. Government has not said anything regarding the situation in Mizoram and Manipur. Yesterday we discussed a Calling Attention Motion by which it was brought to the notice of Govt. the situation in which 22 jawans were ambushed and killed in Imphal. The situation is still not under control. The negotiation with Laldenga, leader of the MNF, has failed and Mizoram rebels are active and already they have collected large funds and arms and ammunitions. But the Government has not mentioned anything about all these matters. They have not told us whether they propose to do anything, what steps they are going to take to meet the situation

there and what solutions they have because after 34 years of independence we have not been able to integrate them in the Indian Union. This is a miserable situation and we should admit it. The President ought to have mentioned this in his Address. This is the position of the law and order situation.

Now, I turn to the economic front. The Government claims that agricultural situation has improved, the foodgrain production has registered an increase in 1980-81 as compared to 1979-80 and also in 1981-82 it is estimated that the production will touch a new high of 133 million tonnes. They have said that they have already brought 5.4 million hectares of land under irrigation and besides this increased land area under irrigation, a large quantity of inputs in the shape of fertilizer and good seeds must have been used. But what is the increase in food production? The achievement would be about one million tonnes over 1978-79 figures. Now, Mr. Chairman, does it not raise certain doubts about the figures? After all, with all these inputs, why should there be an increase of only one million tonnes?

Similarly, with regard to power, they say that there is an increase of 11 per cent and odd. On the day this was announced by the President here, you are aware what the position in Ranchi in regard to power supply was in particular and most part of Bihar in general. Many States have also announced severe power cuts. This is the performance with regard to power generation.

MR. CHAIRMAN: Is it a fact that talking in terms of average at times becomes dangerous and misleading?

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA: Yes, Sir, averages mislead all of us and unfortunately Government depends too much on averages which mislead the people. But you see, as I told you earlier, people of this country will not be misled or hoodwinked for long and if you are not going to give relief to them right now they will revolt. Now, with regard to power generation, I have said that several States like Bihar, Orissa, Rajasthan. Tamil Nadu Karnataka, Goa and Madhya Pradesh have introduced severe cuts. Then Government told us that they were going to add nearly 3000 megawatts of power generation. I do not know what has been the achievement in this field. But the truth is as was reported by "The Economic Times" on January, 12, that with regard to power there is a seepage of 60 per cent to 70 per cent and the Power Ministry has discovered this, most probably, very late.

Now, with regard to capacity utilisation, the Power Minister told the Consultative Committee that the capacity utilisation as was reported graphically in the 'Patriot' of 12th February, had crawled from 49.1 per cent in January last year to 49.7 per cent this year. This is the position of the capacity utilisation of power. In Bihar the situation is still worse. We have Pathratu Power House with a capacity of 600 megawatts. But, Sir, you know its performance. We have Barauni Thermal Power Station. It has a capacity of 245 megawatts.

17.00 hrs.

Sometimes the generation in Barauni is 20 megawats, and in Patratu it goes down to 60 megawatts. Where is the snag? The Government does not seem to go into the whole question, and then they claim that they are increasing power generation and will be able to provide power to the country and all the people. But it appears to me that the Government is not sure of its own performances, otherwise the Industry Ministry would not have allowed many industrial units to set up their own captive power plants. It is because of their own inability to provide them power, their lack of confidence in their ability that they have allowed this. This is a serious matter and should be taken note of.

We always talk of indigenization, but we have no confidence in the indigenous equipment. The Energy Ministry has

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

sought the Cabinet approval for import of equipment against the vehement opposition of BHEL, who are in a position to manufacture equipment for you, but you are not prepared to depend on them and are importing equipment.

As regards steel, the target has been revised to 6.5 million tonnes. The National Herald which is not antagonist to the Congress (I) party reported as recently as 8th February that the revised target of 6.5 million tonnes for the steel may not be achieved. It has expressed its doubts.

With regard to the prices, it has been claimed by the Government that they have succeeded in controlling the inflation and bringing it down to 8 per cent. They have said that the wholesale price index is showing a downward trend, but what is the reality, what is the real picture? It has got no relationship with the reality. Does the consumer price index show the same thing, or is it showing an upward trend? The cost of living index is the barometer of the woes of the common people. If the cost of living index goes up, you cannot claim that you have succeeded in controlling the inflation or the prices. The cost of living index has gone up without any doubt. The first time it went up was in 1974; it was the heaviest and it was boosted up by the oil price hike. Since then it has been going up, and this time it has gone up by 49 points. This is the real position. Even the Economic Review of the Government admits that prices of many consumer goods are very high. The Currency and Finance Report of the Reserve Bank has come out with this conclusion that there is no indication of a halt, in much less reversal of, the inflationary pressure. This is the report of your own institution. And then you claim that you have been able to control the inflationary trends and that the prices are coming down. But this is far from reality.

17.04 hrs.

(Shri Chintamani Panigrahi in the Chair.)

As far as the industrial production is concerned, you have claimed that the production has risen by 8 per cent. it was 4 percent earlier. It has, however, not been explained in so many words how the industrial production picked up like this. Shri Balanandan, while speaking, however, said that the unlicensed capacity of the industrial units which were producing in an illegal manner has been legalised. And the production figures have been added up by taking into consideration the 25 per cent produced by the illegal installed capacity. So, this is the position with regard to the industrial production. While on the one hand you claim increase in production, on all fronts, there is a glut in the market on the other hand. Take the case of steel. The saleable steel is accumulating. You have imported steel also to make up the gap in supply and demand, because you calculated that you will be able to produce about 7 million tonnes and 1.5 million tonnes from the small units. So you needed 1.5 million tonnes more, which you have imported to create a psychology of surplus But, Sir, what is the position today? The saleable steel is accumulating. Unless these steel mills are able to dispose of those stocks they will be put to a great difficulty. Similar is the position in cotton textiles. Even though there has been strike going on in Bombay, still you find there is glut. Then with regard to sugar. Whereas the Government have claimed that sugar-cane production will go up to 180 million tonnes, it is paradoxical that many sugar mills are facing threats of closure. In Maharashtra, about 35 cooperative factories and in UP about 30 mills are facing the threats of closure. This is the economic scene on the basis of which this Government has come forward to claim that during the two years' rule they have made all-round progress and that they have secured achievements.

Now, they want the Opposition should cooperate with them considering the fact that the situation has been complicated because of the presence of military in the Indian Ocean and disturbed international scene. Also because of acquisition of sophisticated weapons by Pakistan and the Iran-Iraq war. They want our cooperation so that the nation can march forward. Yesterday, Shri Ram Jethmalani did offer cooperation on certain conditions. But I have merely to say this that you have to stop accusing the Opposition for everything, you have to stop accusing the Opposition for sabotage and anti-national activities. You should treat them as partners, because in democracy the Opposition and the ruling party are the two wheels of the Government. Unless they go together, the government will not move. So you have to create conducive conditions so that the Opposition offers you its cooperation. And I may assure you, if conducive conditions are created, if appropriate conditions are created, the Opposition will not be lagging behind in helping you to solve the problems which will strengthen our nation.

SHRI R. L. BHATIA: (Amritsar): Mr. Chairman, Sir, I stand to support the Motion moved by Prof. Ranga in thanking the President of India for his Address.

Shri Satyendra Narayan Sinha said that no progress has been made in this country and that nothing has been done since Independence.

I would like to ask him one thing. He was on this side up to 1969 and that he was a Finance Minister in the Bihar State also. What was he doing at that time? Could he say this thing at that time? Now since he is in the Opposition, he is saying differently. He was praising the Janata Rule. Well, he has a right to say so. Everybody has a right to praise one's own deeds and actions. But I think in this country there is a democracy. It is the people who are the deciding factor.

People like Mr. Sinha were elected for five years, but they had to go back after 2-1/2 years; and in the next election, they were defeated. It means that people had no confidence in them after seeing what they did in 2-1/2 years. If Mr. Sinha still insists on what he is saying, I cannot stop him.

Mr. Balanandan is a national leader. He is not present now. I expected that this great leader would speak something positive and give us constructive suggestions, and tell us as the leader of the Opposition, certain failings on our part, so that we may correct them. But he could not rise above the politics of West Bengal and Kerala, and above saying that rice and wheat were not supplied. In respect of these matters, Prof, Roy and others had spoken: and very satisfactory answers have been given by our Ministers with regard to the supply of foodgrains.

I would also like to draw his attention to the Jullunder Resolution of his party in 1978. They sought the cooperation of the communal parties, viz. Rkali Dal. Will it be called a principle? He is attacking us on our principles and policies. Was it his policy to cooperate with communal parties to get power—or to share power with them? Is it opportunism or principle? What is he talking about?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: What are you doing in Kerala, with Muslim League?

SHRI R. L. BHATIA: I am talking to you about your Jullunder Resolution. As far as Kerala is concerned, we want to save democracy.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It is only to fight authoritarianism that we wanted them to cooperate with us.

SHRI R. L. BHATIA: I will come to it also later.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: God save us from the saviours of democracy.

SHRI R. L. BHATIA: He also mentioned about our foreign policy, and said that in the President's Address, no mention was made of the U..S. imperialism. Our actions speak for us, viz. that we are opposed to Diego Garcia, and all types of alliances which America is having in this region. On all the points we have been opposing them thoroughly; but what about China, their friend? They are cooperating with US imperialism and that is why America is building every day more and more in Diego Garcia. (*Interruptions*) Let him deny that China is not their friend. (*Interruptions*)

The present supply of arms to Pakistan is also due to the fact that China supported US. If that had not happened, perhaps America would have thought otherwise. So, it is China's collaboration that is creating problems in this region. (*Interruptions*)

I would like to speak on the positive side, and will not go on criticizing them unnecessarily. I will say that the President has given us a clear picture—where India stands today: the good points, and points where we made progress and where we failed. He has not hidden any fact. For instance, coming to the economic situation, he has said that infra-structure has improved. Some time back when there was shortage of coal and other raw materials, the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi constituted a sub-committee of Cabinet to look into the matter. Since then, what we find is that things have improved. It took us some time when we took over in 1980. It took one year for us to clear the garbage—what the Janata Government had left. And the next year, with these policies which the Prime Minister. Mrs. Indira Gandhi has adopted, the things have started showing results. I do not say that we have succeeded completely, but we are on the way to progress and the figures will tell you that the power generation was increased by 11.3 per cent.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But the electricity is not available.

SHRI R. L. BHATIA: There is more demand. When the demand is increasing, we are trying to cope up with the situation. But the fact remains you cannot hide this fact that the generation of electricity has increased. The coal production has increased by 11.2 per cent and railway goods traffic by 14.4 per cent. With the availability of these things like more electricity, more coal and movement of railway wagons, there has been an increase in the production of the industrial goods. You will be happy to know that steel production has increased by 18.7 per cent due to supply of infrastructure, the cement production has increased to the extent of 15 per cent, nitrogeneous fertilizers to the extent of 51.9 per cent. This did not happen just like this it happened because of the planning, because of the policies adopted by the Congress (I) Government. It is because of the implementation of those policies that this progress has been made.

Three fertilisers plants are coming up. One is in West-Bengal. You are not supplying electricity. If you supply electricity it could function even today. With the functioning of these three plants, I am sure, the production of fertilisers will increase from 45 lakh tonnes to 53 lakh tonnes.

The petroleum product is the major drain on our foreign exchange resources. We are very anxious to increase our petroleum products in India. Seismlogical survey has taken place and we have had contacts with other people, foreigners: and more and more places are being surveyed; and we are glad that now we have a very good prospect in Godavari and Cauvery areas for oil. So far, we have increased the production from 10 million tonnes to 15 million tonnes and we

hope that we will be able to make more progress in this respect. At present, Rs. 5000 crores we are losing by way of foreign exchange for the import of crude oil. If there is more progress in this way, I am sure, we will not have to depend on the import. Even if we import every year, if we produce more, we will save Rs 1000 crores every year; and in the near future, we will be able to come near self-sufficiency.

Similarly, the President's Address has explained the situation in the agricultural sector. We had in 1979-80, 129 million tonnes of foodgrains: in 1980-81, we had 132 million tonnes. Now with the better prospects of this crop—the rains have taken place in time and the seeds have been supplied and more irrigation facilities have been provided we expect that we will be having more than 132 million tonnes of foodgrains: and it will break all the previous records. This has not happened because of this; it has happened because of certain policies adopted by the Congress (I) Government; this is the achievement; this is the development; this is the way that we are going on; and if we go on in this way, I am sure, the country will progress much more.

This progress is there inspite of the fact that we have various impediments. One impediment is that our friends are always trying to have bandh; they are always trying to raise one agitation or the other some times and are unnecessarily wasting the national energy. But, in spite of that, we are marching forward.

Now I come to the policy of the credit. Since we have nationalised banks, we have a major instrument in our hands to direct the credit policy of this country. I am glad that more and more branches have been opened in the villages and in unbanked areas and the credit is supplied to agriculturists and other priority sectors.

There are other spheres where this nation can feel proud of. I am sorry to say that none of the leaders of the Opposition came forward to praise the progress which we have made in the sphere of space. We had three satellites. One satellite is Rohini, our own launching system. Then we have APPLE, our communication system. And we have Bhaskara II which is giving information about the earth. This is a great achievement by our scientists. It is here that they should come forward and say that here is this Government which has encouraged scientific knowledge, science and technology and as a result of this Government's policy, our scientists have been able to achieve this. But they will always take a negative and destructive attitude. We all should praise and congratulate our scientists on this feat.

Similarly, the other day, the Prime Minister made a statement in the House about Antarctica. We are the eleventh country in the world which has performed this job. We should be proud of this achievement. But you do not give us any credit for anything. We are working hard for this nation. We are enhancing the prestige of our nation roof high. We must appreciate those people who are keeping the nation's head high.

I appreciate what Mr. Balanandan has said with regard to the foreign policy. There are many areas where we agree. I may tell you that the Congress (I) Party's policy and Prime Minister Indira Gandhi's policy is one against imperialism. We are in co-operation with the socialist countries and the third world countries. But we are against imperialism. Nobody can deny this fact. It is the Prime Minister Indira Gandhi who went from place to place. She went to Indonesia, Europe, Cancum and other places. Wherever she went, she had created an impression of a world statesman, who could deliver the goods. Today all the non-aligned countries, countries of the third world and all the socialist countries are looking to the Prime Minister Indira Gandhi because she is a factor to be reckoned with in the world today.

[Shri R. L. Bhatia]

I am sorry to say that the people in the opposition do not appreciate her. They are unnecessarily criticising her. But she will play her part in spite of them. This country will march forward in spite of them.

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हमारे माननीय रंगा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं । हार्दिक समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि मैं सरकारी पक्ष का एक सदस्य हूं, बल्कि हकीकत यह है कि सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे अर्थ के पैमाने पर हो, चाहे भूमि सुधार के पैमाने पर हो, चाहे वैदेशिक नीति के पैमाने पर हो, हर क्षेत्र में सरकार का संतोषजनक अचीवमेंट रहा है ।

विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों का एक मौलिक अधिकार है सरकार की आलोचना करना। लेकिन उसके साथ-साथ विरोधी दलों के लोगों का यह भी कर्त्तव्य बनता है कि सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए । लेकिन इन्होंने जो बातें अपने पक्ष की ओर से रखी हैं, वह बेबुनियाद हैं और जिसका कोई आधार नहीं है ।

सभापति महोदय, पिछले बजट सेशन में जो राष्ट्रपति जी ने कहा था कि दो वर्ष में जनता पार्टी और लोक दल की प्रतिक्रियावादी सरकार के चलते यहां की अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी . . . ला एण्ड आर्डर का डिटेरियोरेशन हो गया था । हम इसको सही रास्ते पर लायेंगे और आज हम देखते हैं कि एक साल का जब हम अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि पिछले बजट सैशन में जो हिन्दुस्तान की जनता के सामने अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए वायदे किये थे, उसमें ट्रिमैंडस प्रोग्रेस हुई है ।

राष्ट्रपति जी के भाषण के यह आंकड़े बताते हैं कि हमने बिजली के उत्पादन में 11 प्रतिशत, कोयले के उत्पादन में 11 प्रतिशत, बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 19 प्रतिशत, नाइट्रोजन खाद के उत्पादन में 51 प्रतिशत, सीमेंट के उत्पादन में 15 प्रतिशत और माल ढुलाई में 15 15 प्रतिशत वृद्धि की है ।

उपर्युक्त आंकड़े यह बतात हैं कि अर्थ के मामले में जो हमारी अर्थ-व्यवस्था इन प्रतिक्रियावादियों की वजह से छिन्न-भिन्न हो गई थी, उसमें क्या ट्रिमैंडस प्रोग्रेस नहीं हुई है ? हमारे विपक्ष के सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि दो वर्ष पहले जो स्थिति आपकी थी, क्या उसमें सुधार नहीं हुआ है ? आप भी अपने क्षेत्र से आते हैं और हम भी अपने क्षेत्र से आते हैं । क्या हमने बिजली उत्पादन के पैमाने पर सुधार नहीं किया है क्या यह उत्पादन नहीं बढ़ाया है ? इन बातों पर गौर करना चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या आप इन आंकड़ों से गाइड होते हैं ?

श्री राम स्वरूप राम : शास्त्री जी, पता नहीं आप कहां से गाइड होते हैं ।

सभापति महोदय : राम स्वरूप जी आप चेयरको एड्रेस कीजिए ।

श्री राम स्वरूप राम : उपर्युक्त सुधार इस बात की ओर इंगित करता है कि हमने अपनी अर्थ-व्यवस्था में काफी सुधार किया है और हम अभी भी कठिन परिश्रम के साथ इसमें लगे हुए हैं । हम चाहते हैं कि हम और अधिक उत्पादन करें ।

आप जानते होंगे कि हमारे प्रधान मंत्री ने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये 20-सूत्री कार्यक्रम का नया रूप दिया है। उस में उत्पादन बढ़ाने का पहला प्वाइन्ट है। इसलिये हम ने 1982 वष को उत्पादन वर्ष के रूप में मनाया है। इस उत्पादन वर्ष में चाहे कल-कारखाने से उत्पादित वस्तुएं हों, या कृषि से उत्पादित वस्तुएं हों; इन सभी में हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, लेकिन आप जानते होंगे कि 19 तारीख को विपक्षी लोगों ने क्या साजिश की थी ? हिन्दुस्तान की जनता से खेतों में काम करने वाले खेत मजदूरों से इन लोगों ने कहा कि काम बन्द करो, उत्पादन ठप्प करो। हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, आप के हाथ में कितने मजदूर हैं ? चाहे हिन्द मजदूर सभा हो या जनसंघ के सहयोग से मजदूर संघ बनाकर चलाते हों, उन के इरादे आप देख लीजिये। हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े और ये चाहते हैं कि कल-कारखाने में तालाबन्दी हो, स्ट्राइक हो। हम वैसी भावना को कंडैम करते हैं और हिन्दुस्तान की जनता ने 19 तारीख को इसे कंडैम कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को देखिये।

श्री राम स्वरूप राम : सभापति महोदय, मुझे इन इन्ट्रप्शन्ज का जवाब देना ही होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आप दिवा-स्वप्न मत देखिये कि आप इस गद्दी पर आने वाले हैं। हिन्दुस्तान की जनता कभी आप को माफ नहीं करेगी क्योंकि आप तोड़ फोड़ में विश्वास करते हैं। आप उत्पादन को ठप्प करते हैं, आप स्ट्राइक ओरिएन्टेड यूनियन को चलाने वाले हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने लाठी चलाई, गुंडों को भेजा .....

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप राम : सभापति महोदय, स्ट्राइक ओरियन्टेड यूनियन को यहां की जनता रिजैक्ट करती है और इसका आप ने प्रतिफल 19 तारीख को देखा। (व्यवधान) उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि (व्यवधान)

गया में एन० टी० सी० काटन मिल है। गया औद्योगीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ सका है, लेकिन वहां पर टैक्सटाइल कारपोरेशन की गया टैक्सटाइल एण्ड जूट मिल है, जिस में दो हजार वर्कर्ज काम करते हैं। उस मिल में प्रति दिन 1200 के०जी० उत्पादन होता है। लेकिन जब इन लोगों ने भारत बन्द का नारा लगा कर चुनौती की दी, तो उस मिल के मजदूरों ने कहा कि विरोधी दल के नापाक इरादों को रिजैक्ट करना है और इसके फलस्वरूप उस दिन मिल में तिगुना प्रोडक्शन हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दुस्तान की जनता और कामगर तथा मजदूर स्ट्राइक-ओरिएिन्टड यूनियन नहीं चाहते हैं। ये यूनियनें स्ट्राइक करती हैं, जो देश के प्रोडक्शन को ठप्प करती हैं, उन को बन्द करना चाहिए। (व्यवधान)

मैं इन लोगों की पालिसी का पोस्ट-मार्टम करते हुए बताना चाहता हूं कि ये लोग रूस के दलाल के रूप में हिन्दुस्तान में कम्युनिज्म लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बापू ने जो रास्ता बताया है, उन्होंने जो गाइडलाइन्ज दी हैं, उन के मुताबिक यहां पर समाजवाद की स्थापना होगी। इस देश की जनता रूस के दलालों के रास्ते पर नहीं चलेगी।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। लेकिन इस के साथ ही उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि हमारे चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमारा पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान युद्ध इनवाइट करना चाहता होगा, लेकिन हमारी प्रधान मंत्री ने दुनिया के अनेक मुल्कों में घूम कर कहा है कि हमारा देश शान्ति चाहता है और

[श्री राम स्वरूप राम]

हम इस क्षेत्र में शान्ति बनाए रखना चाहते हैं। हिन्दुस्तान की जनता को, और विरोधी पक्ष के लोगों को भी, इस बात का गौरव होना चाहिए कि इस देश ने श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी शखसियत पैदा की है, जो हिन्दुस्तान की ही नहीं, बल्कि थर्ड वर्ल्ड के तमाम देशों की चैम्पियन हैं। इन लोगों को श्रीमती गांधी के गुणों को स्वीकार करना चाहिए और उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए।

जहां तक हरिजनों का सवाल है, हरिजन का अर्थ है गरीब और गरीब का अर्थ इन्दिरा गांधी होता है। मैं इन्दिरा गांधी को गरीब शब्द से इक्वेट करना चाहता हूं। आज हरिजनों और आदिवासियों की हालत में सुधार करना ही इस देश की मूल समस्या है। जब तक हिन्दुस्तान के हरिजनों और आदिवासियों की हालत में सुधार नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को समाजवादी व्यवस्था में रहने के हकदार नहीं बना सकेंगे। इसी आगस्ट हाउस में जब हरिजनों पर होने वाला जुल्म, उन के कत्ले-आम, उन को जिन्दा जलाने और उन की स्त्रियों के साथ बलात्कार की चर्चा होती है, तो यह आश्वासन दिया जाता है कि हम उन्हें सुरक्षा देंगे। पर हो क्या रहा है, आप जानते हैं कि 95 परसेंट हरिजन और आदिवासी गांवों में पशुओं जैसी जिन्दगी बिता रहे हैं। न उन के पास घर है और न जमीन हैं। हम भटिंडा कांग्रेस से ले कर आज तक प्रस्ताव पास करते रहे हैं कि हम हरिजनों को जमीन देंगे, उन्हें हर तरह की सुविधा और सुरक्षा देंगे। हालांकि हमारा यह इरादा हकीकत में पूरा नहीं हो सका है, लेकिन सरकार उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है।

मैं विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि की हरिजनों की हत्यायें होती हैं, उनके घरों को आग लगाई जाती है और उन की औरतों के साथ बलात्कार होता है, तो वे क्यों चिल्लाते हैं। अगर हरिजनों को जान से मारने और उन्हें जिन्दा जलाने की आदत इस मुल्क में पहले पहल किसी ने डाली, तो वह लोक दल और प्रतिक्रियावादी दलों की सरकार के प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह ने डाली, जिस की शागिर्दी श्री अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। साथ में बैठे हुए मधु दण्डवते जी थे और यह बेलची से चल रहा है। यह चीज हमें विरासत में मिली है और इस को हम कलंक मानते हैं। सरकार की यह मंशा है कि इस देश में तमाम हरिजन और आदिवासी एक न एक दिन सुरक्षित होंगे, इसलिए कि हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, चरण सिंह नहीं हैं। हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी कठिनतम से कठिन रास्ते से चल कर देश की सारी समस्याओं को सुलझा रही हैं तो हम समझते हैं कि हरिजन और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं एक न एक दिन इंदिरा गांधी जी की नजर उन पर भी जायेगी और सदा के लिए हरिजन आदिवासियों पर होने वाले ये अत्याचार बन्द हो जाएंगे।

इसी हाउस में मैं हरिजनों के सवाल को लाया था कि आप जमीन तो उन को बांट रहे हैं, वह बांटें लेकिन एक चीज यह है कि आज भी हरिजन और आदिवासियों के शिक्षित बी० ए०, एम० ए०, मिडिलपास बच्चे देहातों में हल जोत रहे हैं और खेतों में काम कर रहे हैं, उन के लिए जाब की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि आप ने रिजर्वेशन दिया है लेकिन रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ है। आज बी० ए०, एम० ए० पास हरिजनों के बच्चे गांवों में जिस तरह की जिन्दगी बिता रहे हैं वह सब को पता है। इसीलिए प्राइवेट मेम्बर्स रेजोल्यूशन के जरिए मैंने मांग की थी कि हरिजनों के लिए, जो शिक्षित बेरोजगार हरिजन हैं, उनके लिए जाब गारण्टी दें, उन को जाब देने की व्यवस्था करें। उस समय श्री वेंकटसुब्बैया जी के द्वारा यह कहा गया कि हम आप की सारी बातों का काग्निजेंस लेंगे और जाब गारण्टी के लिए जितना

हम से बन सकेगा उसमें कोई कसर नहीं ग्राने देंगे। . . . (**व्यवधान**) . . मेरा यह कहना है कि हरिजन ग्रौर ग्रादिवासियों को शिक्षा को केन्द्र ग्रपने ग्रधीन ले ग्रौर उस को ग्रपनी ही देखरेख में चलाए। जो हरिजन ग्रौर ग्रादिवासी शिक्षित ग्रौर बेरोज़गार हैं उन के लिए कालबद्ध योजना बनाएं ग्रौर संविधान में संशोधन ला कर जाब गारंटी की व्यवस्था करें। प्राइवेट सैक्टर ग्रौर पब्लिक सेक्टर या ग्रन्य दी जाने वाली एजेंसियों में उन के लिए उपयुक्त जगह करें जिस से हरिजन ग्रौर ग्रादिवासी राष्ट्र की मुख्य धारा में ग्रा सकें।

तीसरा सवाल मैं यह रखना चाहता हूं कि मैं बिहार से ग्राता हूं ग्रौर मुझे गौरव है कि बिहार की सरकार ने ग्रोल्ड एज पेंशन की व्यवस्था कर के इतना काम से काम बिहार की धरती पर रहने वाले बूढ़े, बूढ़ियों ग्रौर ग्रपाहिजों का हित किया है ग्रौर ग्राज 20 लाख ग्रोल्ड एज पेंशनधारी बिहार में हैं। उन को 30 रुपये प्रति माह मिलता है वे 20 लाख बूढ़े इंदिरा गांधी को बेटी मान कर कहते हैं कि बेटी के यहां से 30रुपये महीना ग्राएगा। बोलिए शास्त्रीजी, गरीबों की सेवा इंदिरा जी करना चाहती हैं या . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग तो कभी शासन में थे ही नहीं।

ग्राचार्य भगवानदेव : ये राज्य करने के काबिल ही नहीं थे।

सभापति महोदय : ग्राप एक मिनट में खत्म करिए।

ग्राचार्य भगवान देव : ग्राप रोकिए तो उन को रोकिए, इन को क्यों रोक रहे हैं? बखेड़ा तो शास्त्री जी कर रहे हैं।

सभापति महोदय : नहीं, इन का टाइम खत्म हो गया।

श्री राम स्वरूप राम : मैं यह कह रहा था कि हम ऐक्शन में चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था कायम हो ग्रौर ग्राप भाषण में चाहते हैं। ग्राप चाहते हैं कि गाल भी फुलावें ग्रौर हंसे भी, दोनों काम शास्त्री जी, एक साथ नहीं चलता। कमिटमेंट के साथ, डिटरमिनेशन के साथ ग्रगर चाहते हैं गरीबों की सेवा करना तो राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया है उसका ग्राप ग्रांख मूंद कर समर्थन कीजिए ग्रौर ग्रपने संशोधन वापस लीजिए। संशोधन किस बात पर है? ग्राप का भी उद्देश्य है, हरिजन ग्रादिवासियों ग्रौर गरीबों की सेवा करना ग्रौर इंदिरा जी तो गरीबों की चैम्पियन हैं, उन की बात ग्राप क्या करते हैं? उन की बात तो विश्व के बड़े बड़े नेता नहीं करते हैं, हम ग्रौर ग्राप तो साधारण सदस्य हैं?

जब मैं ग्रपने क्षेत्र गया के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। गया एक ऐतिहासिक स्थान है। उसका एक पुनीत इतिहास है। गया एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था कि हिन्दुस्तान में सोशलिज्म कैसे ग्रायेगा। उसी स्थान के सम्बन्ध में मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। ग्रौद्योगिक नक्शे में गया का स्थान बहुत ही पिछड़ा हुग्रा है। जो इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड स्थानों की लिस्ट है उसमें भी उसका नाम है। मेरा ग्रनुरोध है कि वहां पर एच० एम० टी० का एक कारखाना खोला जाए। वहां पर जो 25 लाख की ग्राबादी है उसमें ग्रधिकतर गरीब लोग ही हैं। 1975 में बिहार सरकार ने एक नायलान फैक्टरी का प्रपोज़ल भेजा था लेकिन पता नहीं वह प्रपोज़ल कहां खटाई में पड़ा हुग्रा है?

इसके साथ साथ मैं सिंचाई के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना चाहता हूं क्योंकि खाद्योत्पादन में उसका बड़ा महत्व है। गया में केवल 15 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है ग्रौर शेष 75 प्रतिशत से ग्रधिक भूमि ग्रसिंचित ही है। मोहाने रेजिवयिर योजन 1975 में ही भारत सरकार को सौंपा

[श्री राम स्वरूप राय]

दी गई थी—मैं जानना चाहूंगा उसकी आज क्या स्थिति है ?

इन शब्दों के साथ रंगा जी ने यहां पर जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हार्दिक समर्थन करते हुए मैं मांग करूंगा कि हरिजन तथा आदिवासियों के लिए एक सेप्रेट डिपार्टमेंट की स्थापना की जाए तथा देश के टोटल बजट का 25 प्रतिशत उन लोगों के डेवलपमेण्ट पर लगाया जाए । धन्यवाद ।

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack): Supporting the Motion moved by Prof. Ranga, I thank the President of India for his illuminating address which aptly summarises the problems and perspectives before the nation and the strategies of progress outlined in his speech.

The nation to-day stands on the cross-roads of progress. As all of you know, the country had to pass through nearly three years of drift during the tenure of the last Government. During the period, chaos and tension had mounted and the economy was in utter shambles. The edifice of progress built under the guidance and leadership of our beloved Prime Minister was considerably weakened. The period since 1980 has therefore, been a difficult period of repair and reconstruction. Under her able leadership the nation has again been put back on the path of progress. Substantial progress has been achieved in developing suitable infrastructure in core sectors. Appreciable achievement has been recorded in power generation, production of coal, steel, fertilizer, cement and transportation by railways and new units now being set up would substantially add to the capacity. An imaginative strategy has been evolved for expanding the indigenous production of petroleum. This will reduce our dependence on the imported oil to a considerable extent. Emphasis has been laid on the promotion of export and the substitution of imports. These measures are bound to have very good effect in curbing the trade deficit Careful planning and substained efforts would improve our food production to a record figure of 132 million tonnes durnig 1981-82. The national income during 1980-81 has recorded an increase of 19.4 per cent in absolute terms and 7.7 per cent in real terms. Net domestic saving has also shown an appreciable increase. Considerable progress has been achieved in the field of science and technology. The scientists are being encouraged. If we had not made the demonstration on the desert of Rajathan at that time, we would not have expected that much confidence in our scientists today. The capability of the scientists is not for war.

The annual rate of inflation has declined and has been brought under control. A new consciousness has emerged for protection and management of environment and ecological balance thanks to the consious efforts undertaken by the Government. Development of alternate sources of energy—renewable energy—has received the importance and priority it deserves. A comprehensive plan for harnessing bio-gas, wind and solar energy has been launched. From all these, one can feel the atmosphere of optimism. We are proud that the President has voiced this optimism in his speech.

Mr. Chairman Sir, the year 1982 is rightly being observed as the "Productivity Year". Productivity is the key to our survival and progress. It is heartening to note that a legislation is being introduced to amend labour laws to create more cordial and congenial condition for work in industrial establishments.

The country today faces considerable external challenges. The threat of war from our western border and the misguided policy of the United States

of America has complicated our problems. Massive supply of sophisticated weapons to Pakistan has compelled us to divert developmental plans for matching the defence needs. We are grateful to our Prime Minister for launching a successful diplomatic offensive which has countered these moves to a considerable extent and have won us many friends.

The sanction of the I.M.F. loan in the teeth of opposition by the United States is an instance of the Prime Minister's diplomatic victory. I would like to point out some of the things for the opposition. Inside the country we see today a desparate attempt by the discredited opposition to unite against the Government with the sole objective of creating instability. The so-called unite move is not based on ideology or programmes but could be termed as a marriage of convenience. We also see some communal political parties and groups trying to ferment trouble, disunity and group confrontation in different parts of the country. The Government must be credited with alertness in handling the situation. We must also be grateful to our conscious millions who have rejeted these moves. The total rejection of Bharat Bandh launched on 19th January is an example of our people's wisdom. I do not find an evidence of wisdom among our Opposition parties. They want to revive the Janata Party. Obviously, the history has no lesson for them to learn.

The Prime Minister has recently given to the nation a charter of progress, a new 20-point programme. This is a document of action with twin objectives, to increase the growth with social and economic justice. Here also, the members in the Opposition can see that this is not a programme for one party. This is for the nation's development and for the welfare of millions of down-trodden and poor people in the far-flung rural areas of the country.

Here again the Opposition is taking a parochial view. They cannot rise above their petty interest and look into the general interest and the general welfare of the country. However, with massive support of the people for this programme, this can usher in a socio-economic revolution in the country.

With these words, once again, I support the motion moved by Prof. Ranga.

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय सभापति जी, इस माननीय सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य प्रो० रंगा साहब द्वारा प्रस्तावित किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, किसी भी देश की राजनीति में, किसी भी देश की प्रगति में, किसी भी देश को उच्च शिखर पर ले जाने के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिये हम भूतकाल की अनुभूतियों पर ध्यान देते हैं और भूतकाल की अनुभूतियों पर ध्यान देते हुये हम वर्तमान को निहारते हैं, फिर दोनों अनुभूतियों का समन्वय करके भविष्य का निर्माण करते हैं । इस प्रकार से इस माननीय सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है । इस दृष्टि से मैंने इस अभिभाषण का जो अध्ययन किया है उस से ऐसा मालूम होता है कि देश को प्रगति की तरफ ले जाने के लिये, राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिये, देश की आर्थिक अवस्था को ठीक करने के लिये, देश के वैज्ञानिक उत्थान को आगे बढ़ाने के लिये, देश की कृषि को आगे बढ़ाने के लिये, देश की शिक्षा को समन्वित रूप देने के लिये, देश में स्वास्थ्य के प्रति या देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये, सभी विषयों को इस में छूने का प्रयास किया गया है । इसीलिये मैं इस के समर्थन के लिये तैयार हुआ हूं ।

[श्री महावीर प्रसाद]

मैंने इस अभिभाषण का पूरा अध्ययन किया है और मुझे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी गुप्त की एक कविता याद आती है—

पीछे पितर पृष्ठ पोषक हैं,
पर भविष्य तो आगे,

यदि अपना परिणाम न देखें
तो हम अंध अभागे ।

उधर बैठे हुये जो माननीय सदस्य हैं, उनके भाषणों को मैंने ध्यान से सुना था चाहे वे श्री राम जेठमलानी हों या श्री बालानन्दन जी और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे मानीय सदस्य, जो बिहार से संबंधित हैं श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ने जो भाषण दिया था, उस को मैंने बड़े गौर से सुना । उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किये और वे यह मानते हैं कि बिजली की पैदावार बढ़ी है । उन्होंने स्वयं कहा है कि बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और यह 11.3 प्रतिशत बढ़ी है । उन्होंने यह भी माना कि कोयले का जो उत्पादन हुआ है उसमें बढ़ोतरी हुई है और वह 11.2 प्रतिशत बढ़ी है । उन्होंने यह भी माना है कि रेलवे के द्वारा जो माल की ढुलाई हुई है, उसमें 14.4 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है । उन्होंने यह भी माना है कि बिक्री योग्य इस्पात का जो उत्पादन है, उस क्षेत्र में विस्तार न होने पर, काफी मात्रा में उस का उत्पादन हुआ है और 18.7 प्रतिशत की उसमें बढ़ोतरी हुई है । उन्होंने यह भी माना है क नाइट्रोजन वाली खाद के उत्पादन में 51.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है । उन्होंने यह भी माना है कि कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है, वह 61.2 प्रतिशत है । उन्होंने यह भी माना है कि पेट्रोलियम संबंधी चीजों के उत्पादन में 18.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है । जब उन्होंने यह माना है कि इन सब के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी कहते है कि बढ़ोतरी बड़ी धीमी गति से हुई लेकिन मैं बड़ी सौम्यता के साथ, नम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था ? उन्नति की तरफ ले जाने की बजाय वे देश को अधोगति की तरफ ले गये और उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई । अब 2 वर्षों से जो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है, यह समुन्नत सरकार है, जिसने न केवल हिन्दुस्तान में वल्कि पूरे विश्व में एक क्रांति की लहर पैदा की है । श्रीमती इंदिरा गांधी ने कानकुन सम्मेलन में जाकर हिन्दुस्तान के गौरव को बढ़ाया और शिखर सम्मेलन में विश्व के विकासशील, विकसित और अविकसित देशों के बीज में जो एक गरीबी की खाई है, उस गरीबी को दूर करने के लिये आवाज उठाई । मैं यह जानना चाहता हूं कि ढाई वर्ष के अन्दर विरोधी दलों की जो सरकार बनी थी, उसने क्या किया था । (व्यवधान) . . . शास्त्री जी, और प्रोफेसर साहब, आप जरा धैर्य से मेरी बातों को सुनें । मैं जानता हूं कि आप अध्यापक हैं और मैं भी अध्यापक हूं । बच्चों को पढ़ाने के लिये बड़ी सौम्यता होनी चाहिये (व्यवधान). आप हृदय से, दिमाग से और मस्तिष्क से सुनेंगे, तब जाकर असर पड़ेगा ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मुद्रा स्फीति की बात करते हैं । किसी भी देश की आर्थिक अवस्था वहां की मुद्रा-सफीति से नापी जा सकती है । 12 जनवरी, 1980, जबकि देश में इन की सरकार हटी थी और हमारी सरकार आई थी, 22.2 प्रतिशत मुद्रा-स्फीति थी लेकिन 10 जनवरी, 1981 को वह घट कर 14.8 प्रतिशत हुई है और पुनः वह घट कर अभी अभी 9 जनवरी, 1982 को 6.9 प्रतिशत रह गई है ।

आप अन्दाज लगा सकते हैं, आप तौल सकते हैं कि इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो नीति है, उसके कारण देश में मुद्रास्फीति कम हुई है। इस सरकार की जो प्रगति है वह आगे चलने वाली है। हमारे विरोध पक्ष में माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान देने की कोशिश करें।

MR. CHAIRMAN: Would you like to continue tomorrow ?

श्री महावीर प्रसाद : जी हां :

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to reassemble tomorrow at 11.00 a.m.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 25, 1982/Phalguna 6. 1903 (Saka).

GMGIPMR—M—3536 LS—16-4-82—890.